मार्च - 2025 वर्ष -10 अंक - 3

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

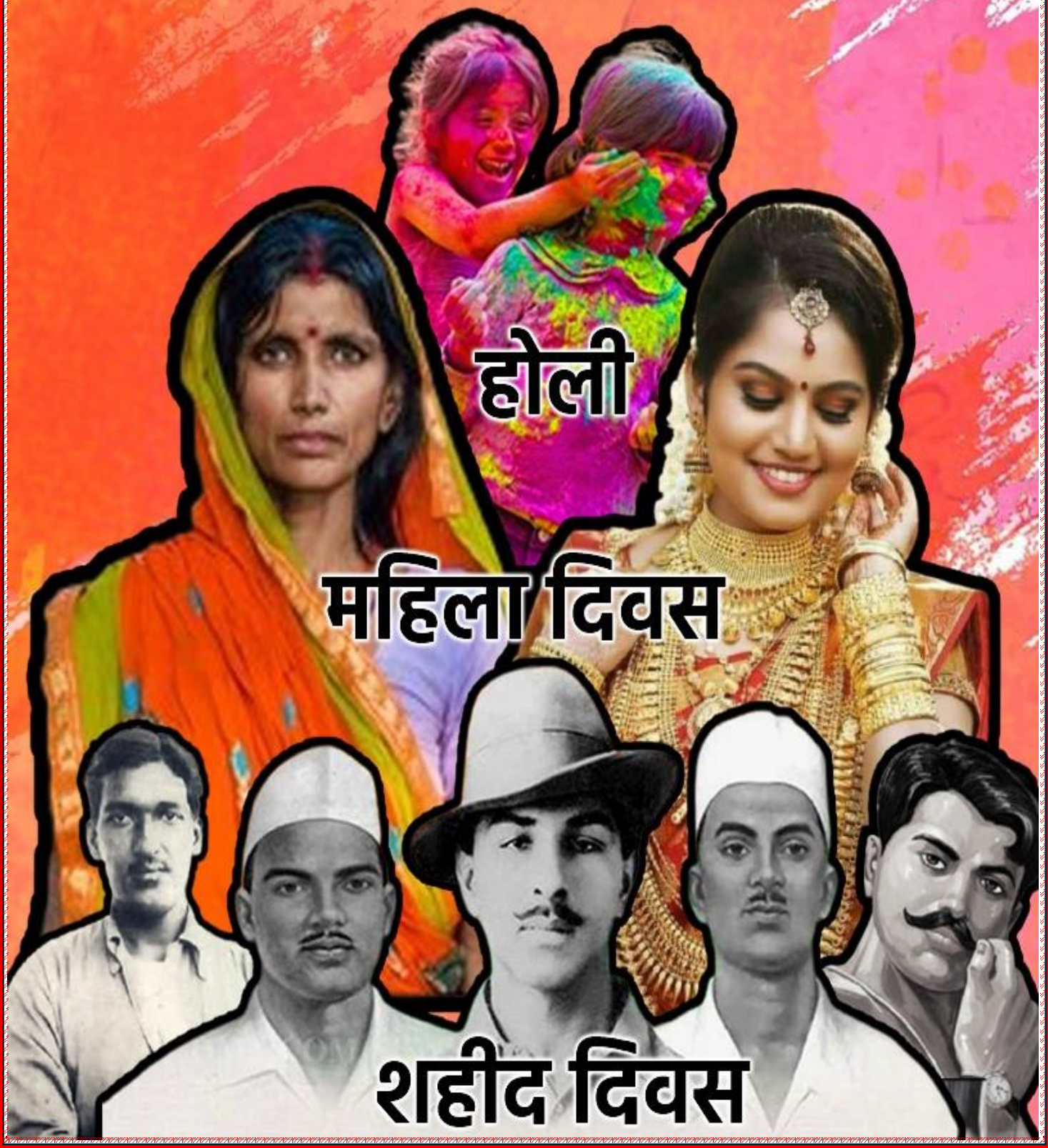

शुल्क - 50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

MEDIA MAP
A Watchdog Of Liberal Democracy

सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक :प्रो प्रदीप माथुर
संयुक्त संपादक : डॉ सतीश मिश्रा
सहयोगी संपादक : प्रो शिवाजी सरकार
विशेष प्रतिनिधि : राजीव माथुर
मुख्य सह-संपादक : प्रशांत गौतम
सह-संपादक : अंकुर कुमार
लखनऊ संवादाता : ज़ेबा हसन
पटना संवादाता : अजय यायावर
रायपुर संवादाता : संदीप कुमार सिंह

मुख्य प्रबंधक :जगदीश गौतम
विधि परामर्शदाता :संजय माथुर

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 ,
वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम
गाजियाबाद-201014

दूरभाष - 9810385757 / 9910069262

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-editor@mediamap.co.in

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से मुद्रित एवं मकान नंबर 70, ज्ञानखंड 4, इंदिरापुरम, जनपद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित. सभी विवादों का निस्तारण जिला न्यायालय गाजियाबाद होगा ।

लेखों में उल्लेखित विचार लेखक के अपने हैं। लेखों और विचारो को लेकर विवाद होने पर पत्रिका के संपादक और प्रकाशक, मुद्रक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय गाज़ियाबाद ही होगा। इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, सहयोगी और लेखक अवैतनिक हैं। पीआरबी एक्ट के तहत अंतर्गत संपादक प्रो प्रदीप माथुर उत्तरदायी है।

संपादकीय		
पत्र पाठको के		
एक झलक पिछले अंक की		
विचार प्रवाह		
दृष्टिकोण		
गिग इकॉनमी से श्रमिक अधिकारों का हनन	प्रो शिवाजी सरकार	8
राजनीति परिदृश्य		
महाकुंभ और भाजपा की चुनावी संभावनाएं	प्रो प्रदीप माथुर	10
कांग्रेस फीनिक्स की तरह राख से उभर रही है।	आर के मिश्रा	12
पूर्व बीजेपी मंत्री का सावरकर, हिंदुत्व पर प्रहार	हमारे संवाददाता द्वारा	16
राज्यों से		
केजरीवाल की राह पर चलते प्रशांत किशोर	प्रो.हेमंत कुमार सिंह	18
देश - विदेश		
अमेरिका के विरुद्ध एकजुट होते पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश	डॉ. सलीम खान	21
मार्च 8 : महिला दिवस		
क्या महिलाओं के अधिकार और समाज में उनका स्थान गंभीर खतरे में है?	डॉ. सतीश मिश्रा	23
महिला सशक्तिकरण: संघर्ष और सफलता	इंदु रानी सिंह	26
मार्च 23 : शहीद दिवस		
उन क्रांतिवीरों की कुर्बानी जिनका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता	प्रशांत गौतम	28
श्रद्धांजलि		
व्यंग्यकार अनूप श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि	अंकुर कुमार	30
पुस्तक समीक्षा		
कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण	मीडिया मैप नेटवर्क	31
कथा साहित्य		
एक दिव्य पुरुष	दिनेश नारायण वर्मा	32
अंदाज़-ए-लखनऊ		

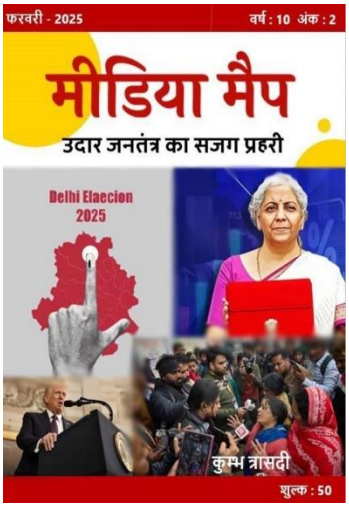

एक झलक पिछले अंक की

आर्थिक मंदी और ट्रम्प का रुख वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौतियां

बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है, क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने, खपत को बढ़ावा देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और धीमी अर्थव्यवस्था पर चिंताओं के बीच भारत के विकास को आगे बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझना होगा। ~ ***प्रो शिवाजी सरकार***

****

भारतीय राजनीति के विलक्षण पुरुष अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति की एक अनबूझ पहेली हैं। एक बड़े सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ वह सूचना अधिकार की मुहिम के साथ जुड़े, फिर वह अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सीढ़ियों चढ़कर राजनीति के क्षेत्र में आए। यकायक चुनाव के मैदान में उतरकर उन्हें आशातीत सफलता मिली तथा वह देश के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि उनका राजनीति में अहम और विकास कैसे और किन कारणों से हुआ? ~ ***प्रो प्रदीप माथुर***

****

कुंभ और गंगा सागर: राजनीतिक टकराव का कारण बने दो पवित्र आयोजन

भारत में आध्यात्मिकता को राजनीति से अलग माना जाता रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि पवित्र अवसर भी राजनीतिक प्रभाव से अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला और पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला के बीच प्रतिस्पर्धा उभरकर सामने आई है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पश्चिम बंगाल सरकार के बीच यह टकराव धार्मिक महत्व, संसाधनों और मान्यता को लेकर है। ~ ***प्रभजोत सिंह***

****

भारत और राष्ट्रपति ट्रंप की नई अर्थव्यवस्था

भारतीय नीति निर्माताओं, चाहे वे विपक्ष में हों या सत्तारूढ़ दल में, को अमेरिका के बारे में अपनी वर्तमान धारणा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, और 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत के प्रति अमेरिकी नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ~ ***गोपाल मिश्रा***

****

सहानभूति के पात्र या माथे का कलंक।

(जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी है—जन्म देने वाली माँ और पोषण करने वाली मातृभूमि स्वर्ग के समकक्ष है।)

देश की स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ियाँ ने "जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अपमान है, "वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है" जैसे राष्ट्रवादी गीतों को गुनगुनाकर अपना विद्यार्थी जीवन जिया था, बड़े होकर वे आजीवन समाजोन्मुखी रहे।

स्वतंत्रता संग्राम में जनित त्याग, बलिदान और सामाजिक सरोकार की भावना समय के साथ-साथ देश के सामाजिक आर्थिक विकास के संघर्ष में परिवर्तित हो गई। आज के युवा अपने पिता और पितामह की तरह देशभक्ति के गीत तो नहीं गुनगुनाते, परंतु भारत को एक आधुनिक और विकसित आर्थिक शक्ति बनाने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं।

लेकिन ये लोग कौन हैं जिन्हें ना जन्मभूमि से कोई लगाव है और ना ही इसके विकास में दिलचस्पी? भावना शून्य ये लोग निजी स्वार्थ, धन और विलासपूर्ण जीवन जीने की चाह में येन-केन-प्रकारेण, परिवार और समाज के सब मानवीय संबंधों को तोड़कर देश से भागना चाहते हैं। यह लोग जानते हैं कि इनके पास विदेश जाने और वहाँ प्रवास करने के लिए कानूनी अनुमति नहीं है, फिर भी ये लोग फर्जी ट्रैवल एजेंट्स की सहायता से अपना सारा धन लुटाकर किसी भी तरह देश छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं।

क्या ऐसे घिनौने, स्वार्थी लोग हमारी सहानुभूति के पात्र हैं? क्या वास्तव में बेइज्जत करके अमेरिका से निकाले गए और बाँधकर वापस भेजे गए लोगों के लिए हमें दुखी होने की आवश्यकता है?

आज भारत विश्व के लिए मानव संसाधन का एक बड़ा स्रोत बनकर उभर रहा है। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक और कौशल दक्ष कार्यकर्ता विश्व के तमाम देशों में कार्यरत हैं और उनके विकास में सहायता दे रहे हैं। बड़े-बड़े पदों पर आसीन यह भारतवंशी हमारे देश का गौरव हैं।

परंतु बिना योग्यता के अवैध तरीके से निजी स्वार्थवश विदेश में घुसे ये लोग ना सिर्फ कानून की नजर में अपराधी हैं, बल्कि निम्न मानसिकता और मूल्यहीन जीवन के भी दोषी हैं। किसी सहानुभूति या दया के स्थान पर ये लोग देश को अपमानित करने के अपराधी हैं।

यह आवश्यक है कि अवैध प्रवास और इसे सुगम बनाने वाले विमान ट्रैवल एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन साथ ही साथ बड़ी चुनौती उस मानसिकता को दूर करने की भी है जो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। आवश्यकता है कि देश के बालमन और नवयुवा समाज में राष्ट्रीय गौरव और देशप्रेम की भावना पैदा की जाए।**~प्रो प्रदीप माथुर**

****

राष्ट्रपति ट्रम्प के विरोध में उठते स्वर

डॉ. मोहम्मद इक़बाल उर्फ़ अल्लामा इक़बाल की यह बात अमेरिकी समाज पर सटीक बैठती है कि "ज़िंदा क़ौमें सौ साल तक इंतज़ार नहीं करतीं।" डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद उनकी नीतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

इन विरोध प्रदर्शनों में प्रवासियों के निर्वासन, ट्रांसजेंडर अधिकारों की वापसी और गाजा पट्टी से फलस्तीनियों को जबरन स्थानांतरित करने के प्रस्तावों की निंदा की गई। ट्रंप के गाजा संबंधी बयानों से लोग असंतुष्ट हैं, जिससे अमेरिका में विरोध बढ़ रहा है।

'मूवमेंट 50501' के तहत 5 फरवरी को फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, इंडियाना सहित 50 राज्यों में एक साथ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और उनकी जाँच की माँग की।

प्रदर्शनों में एलन मस्क और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की भी आलोचना हुई। ट्रेजरी विभाग के वर्गीकृत डेटा तक एलन मस्क की पहुँच पर चिंता जताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई।

सोशल मीडिया पर भी ट्रंप का भारी विरोध हो रहा है। लोगों ने #BuildTheResistance और #50501 जैसे हैशटैग के साथ आंदोलन तेज कर दिया। '50501' हैशटैग के तहत एक ही दिन में 50 राज्यों में 50 विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया गया। कई वेबसाइटों और अकाउंट्स पर 'फासीवाद को अस्वीकार करें' और 'हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें' जैसे संदेश फैलाए गए।

अमेरिका में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग सड़कों पर डटे रहे और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराते रहे।

इस बीच, ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की, लेकिन वार्ता विफल रही। हालांकि, उन्होंने मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को एक महीने के लिए रोकने का ऐलान किया, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर के टलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ज़िंदा लोग अपने अस्तित्व का प्रमाण देते रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन मुर्दे और मूर्ख कभी नहीं जागते। (~ **श्याम सिंह रावत)**

****

ऐ.आई. के बाजार को बदलती चीन की तकनीकी रणनीति

अमेरिकी शेयर बाजार में हालिया गिरावट के लिए चीनी AI कंपनी डीप सीक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर AI में नेतृत्व परिवर्तन पर बहस छिड़ गई है। अब तक अमेरिका Google, Microsoft और OpenAI जैसी कंपनियों के जरिए AI में अग्रणी रहा है, लेकिन डीप सीक की सफलता ने इसे गंभीर चुनौती दी है।

डीप सीक के प्रभाव से अमेरिकी बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे निवेशकों में चिंता और टेक कंपनियों की भविष्य की लाभप्रदता पर सवाल खड़े हो गए हैं। चीन की सरकार द्वारा भारी निवेश और विशाल डेटा तक पहुंच ने उसकी AI

कंपनियों को तेज़ी से विकसित होने में मदद की है। चीन के ढीले डेटा गोपनीयता नियमों के चलते AI मॉडल के प्रशिक्षण में उसे बढ़त मिल रही है, जिससे वह चेहरे की पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और स्वायत्त वाहनों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

AI केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है। डीप सीक की सफलता चीन की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम मानी जा रही है, जिससे अमेरिका-चीन के बीच आर्थिक अलगाव की आशंका बढ़ गई है।

AI विकास के साथ नैतिक और नियामक चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता और एल्गोरिदम पूर्वाग्रह जैसे मुद्दे शामिल हैं। AI शिक्षा और कार्यबल विकास पर जोर देना अब देशों की प्राथमिकता बन गई है।

डीप सीक का उभरना केवल अमेरिका के प्रभुत्व के लिए खतरा नहीं, बल्कि वैश्विक विज्ञान और तकनीक में बड़े बदलाव का संकेत है। यह AI अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जिससे विश्वभर में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। (**~ शेख सलीम)**

****

मोदी सरकार और डेटा: एक असहज रिश्ता

जनवरी 29 को प्रयागराज महाकुंभ में हुई मौतों की सही संख्या सरकार द्वारा छिपाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पारदर्शिता के बजाय आंकड़े दबाने को प्राथमिकता देती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सरकार डेटा एकत्र करने से बचती है और उपलब्ध डेटा को हेरफेर कर प्रस्तुत करती है। डेटा को 21वीं सदी की नई संपदा माना जाता है, लेकिन सरकार इसकी पारदर्शिता से परहेज करती है। उदाहरण के लिए, 2018 में जीडीपी गणना के आधार वर्ष को बदलकर यूपीए सरकार की विकास दर को कम दिखाया गया।

नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, लेकिन सरकार ने इसके प्रभाव से जुड़े वास्तविक आंकड़े छिपाए। कोविड-19 से मौतों की सही संख्या भी अज्ञात है, क्योंकि सरकार ने डब्ल्यूएचओ के 4.7 मिलियन मौतों के अनुमान को खारिज कर दिया, लेकिन कोई वैकल्पिक आंकड़ा पेश नहीं किया।

जनगणना, जो 2011 में हुई थी, अब तक नहीं हुई है, जिससे योजनाओं को सही ढंग से लागू करना मुश्किल हो रहा है। जातिगत जनगणना की मांग को भी सरकार ने अनसुना कर दिया, जिससे नीति निर्माण प्रभावित हो रहा है।

सरकार की "कोई डेटा उपलब्ध नहीं" नीति प्रशासनिक पारदर्शिता को कम करती है। डेटा के अभाव में नीतिगत फैसले कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे घरेलू नीति और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता प्रभावित होती है। (**~ डॉ. सतीश मिश्रा)**

****

मणिपुर : बजट कटौती या आर्थिक दण्ड

केंद्रीय बजट 2025-26 में हिंसा प्रभावित मणिपुर के आर्थिक पतन और मानवीय संकट से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए। राज्य को एक विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत थी, लेकिन इसमें कोई ठोस राहत नहीं दी गई।

लंबे समय से जारी हिंसा ने मणिपुर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है और आय में भारी गिरावट आई है। एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं।

बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹3.4 लाख करोड़ की कटौती की गई है। कुल व्यय ₹47.16 लाख करोड़ तय किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹1 लाख करोड़ कम है। मनरेगा का बजट भी घटाया गया, जिससे मणिपुर में कार्यदिवस 100 से घटकर मात्र 35 रह गए हैं।

इस कटौती से गरीब और ग्रामीण समुदायों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी। मणिपुर को शांति और विकास के लिए विशेष सहायता की जरूरत थी, लेकिन बजट ने उसकी अनदेखी की है। **(~ शिवाजी सरकार)**

****

"अपमानजनक निर्वासन" पर भाजपा में तकरार

अमृतसर हवाई अड्डे पर पिछले शनिवार को 119 अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिका से दूसरा विमान उतरने के बाद निर्वासन के बंदरगाह के चयन को लेकर विवाद बढ़ गया। एनडीए और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं।

पहले बैच में 30 और दूसरे बैच में 67 पंजाब के लोग थे। अन्य राज्यों में हरियाणा (33), गुजरात (8), यूपी (3), गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान (2-2), हिमाचल और जम्मू-कश्मीर (1-1) शामिल हैं। जल्द ही तीसरा अमेरिकी विमान भी उतरने की उम्मीद है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर पंजाब को बदनाम कर रही है। उन्होंने पूछा कि अमृतसर को ही निर्वासन के लिए क्यों चुना गया, जबकि दिल्ली जैसे अन्य विकल्प भी उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है मानो केवल पंजाबी ही अवैध अप्रवासी हैं।

भाजपा नेता आरपी सिंह ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अमृतसर अमेरिका के सबसे नजदीकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, इसलिए निर्वासितों को वहीं उतारा जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर आपत्ति जताई।

इस बीच, ट्रंप प्रशासन का "निर्वासन अभियान" जारी रहने की संभावना है, जिससे पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। **(~ प्रभजोत सिंह)**

****

भाषिक दरिद्रता से भाषाई सांप्रदायिकता तक

यह लेख भारतीय राजनीति में भाषा के गिरते स्तर और उसके सांप्रदायिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। हाल के वर्षों में संसद, विधानसभाओं, रैलियों और सोशल मीडिया में असंसदीय और अभद्र भाषा का बढ़ता उपयोग

हमारी सभ्यता और संस्कृति पर सवाल खड़ा करता है। दुर्भाग्यवश, इस प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई ठोस विरोध नहीं दिखता, बल्कि ऐसी भाषा का उपयोग करने वालों को प्रोत्साहन और राजनीतिक लाभ मिलता है।

'इंडिया हेट लैब' की रिपोर्ट भी दिखाती है कि चुनाव जीतने और सत्ता पाने के लिए नफ़रत फैलाने वाली भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। पहले राजनीति में व्यंग्य और कटाक्ष मर्यादित रहते थे, परंतु आज व्यक्तिगत आक्षेप और अपमानजनक शब्द आम हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की शालीन भाषा और व्यंग्यात्मक शैली को याद करें, तो वर्तमान राजनीति में भाषा का स्तर बेहद गिर चुका है।

अब इस भाषाई गिरावट के साथ सांप्रदायिकता भी जुड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू को कठमुल्लों की भाषा बताने जैसे बयान इसका उदाहरण हैं। उर्दू और हिंदी का गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है, और इसे केवल एक समुदाय से जोड़ना न सिर्फ भाषाई विभाजन को बढ़ावा देता है बल्कि भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाता है।

भाषा का यह सांप्रदायिक और अमर्यादित स्वरूप चिंताजनक है। साहित्यिक समाज को इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। **(~ जय चक्रवर्ती)**

****

मोदी-ट्रम्प वार्ता: भारत के लिए लाभ और चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों से घिरी रही। अमेरिका द्वारा भारत के टैरिफ नीतियों पर सवाल उठाने के बावजूद, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

ट्रम्प ने भारत के उच्च टैरिफ पर आपत्ति जताई और पारस्परिक शुल्क लगाने की चेतावनी दी। मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च मानने की ट्रम्प की नीति की सराहना की। भारत 500 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत अमेरिका से कच्चा तेल, हथियार और अन्य उत्पाद खरीदने को तैयार है।

अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर की पेशकश की, लेकिन इसकी ऊंची लागत और भारतीय रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रभाव को लेकर संदेह बना हुआ है। भारत ने 4 बिलियन डॉलर में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए 200 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने की योजना बना रहा है, जिससे रूस पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है।

भारत ने अमेरिकी पेट्रोलियम आयात को 15 से 25 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। अमेरिका भारत के लिए शीर्ष तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बनना चाहता है, लेकिन इससे पश्चिम एशिया के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका प्रभावित होगी। अमेरिका से LNG आयात महंगा है, लेकिन इसकी भरपाई कम कीमत से हो सकती है।

भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा है, जबकि पश्चिमी देश इसे कम कर रहे हैं। इज़राइल-गाजा युद्ध से भारत के डीएपी उर्वरक आपूर्ति पर असर पड़ा और IMEEC परियोजना बाधित हुई।

मोदी की यात्रा से भारत को ठोस लाभ कम दिख रहे हैं। टैरिफ विवाद जारी रहेगा और अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता बढ़ सकती है। F-35 सौदे पर भी गहन समीक्षा होगी, क्योंकि भारत ने इसे खरीदने की पहल नहीं की थी। (**प्रो शिवाजी सरकार)**

गिग इकॉनमी से श्रमिक अधिकारों का हनन

प्रो शिवाजी सरकार

भारत की अर्थव्यवस्था, जो अपनी गति पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, एक नई चुनौती का सामना कर रही है। यह चुनौती है गिग वर्कर्स की बढ़ती संख्या, जिन्हें नीति आयोग जैसे संस्थान सम्मानित श्रमिकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये गिग वर्कर्स, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते कार्यबल का हिस्सा हैं, अक्सर अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं। नौकरी खोने और भुखमरी के डर से, कई श्रमिक अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में असमर्थ रहते हैं।

गिग इकॉनमी, जिसमें स्थायी रोजगार की तुलना में अस्थायी अनुबंध और फ्रीलांस अवसर शामिल हैं, को देश के थिंक टैंक ने "प्रगतिशील बदलाव" के रूप में पेश किया है। हालांकि, श्रमिकों के लिए यह मॉडल सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी, तनावपूर्ण कार्य शेड्यूल, और असुरक्षा लेकर आता है। कंपनियां कम लागत और सीमित देनदारियों का लाभ उठाती हैं, लेकिन इसका श्रमिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति से यह सीखा जा सकता है कि बेरोजगारी और युवा असंतोष किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

> भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। अस्थिर रोजगार, कम वेतन और शोषण जैसी चुनौतियां गंभीर हैं। सरकार को इस असमानता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

नीति आयोग के अनुसार, 2020-21 में भारत का गिग वर्कफोर्स 7.7 मिलियन था, जो 2029-30 तक 23.5-30 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, गिग वर्क को रोजगार के सबसे निचले स्तर के रूप में देखा जाता है। गिग वर्कर्स को बीमार अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। इसके बावजूद, आयोग इसे "मुक्त बाजार प्रणाली" के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय ने हाल ही में श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर 44 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बदल दिया है। यह बदलाव श्रमिकों के लिए न्याय और सुरक्षा प्राप्त करना और भी कठिन बना देता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उबर, और ओला जैसी कंपनियां गिग इकॉनमी का प्रतीक हैं। ये कंपनियां अपने श्रमिकों से अधिक काम करवाती हैं, लेकिन बदले में उन्हें उचित लाभ नहीं देतीं। अमेरिका और अन्य विकसित देशों में भी गिग इकॉनमी की खामियां उजागर हुई हैं। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी अदालत ने अमेज़न पर श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए $5.9 मिलियन का जुर्माना लगाया।

भारत में भी, मदुरै उपभोक्ता आयोग ने अमेज़न और अन्य

कंपनियों पर मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने की मांग की है।

भारत में बेरोजगारी अभी भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, 2020-21 में युवा बेरोजगारी दर 12.9% थी, जो 2022-23 में घटकर 10% हो गई। हालांकि इसमें कमी आई है, लेकिन रोजगार सृजन की गति धीमी है।

गिग वर्कर्स की औसत आय लगभग ₹15,000 प्रति माह है। मुद्रास्फीति दर 6-9% और घटती जीडीपी वृद्धि से श्रमिकों की स्थिति और खराब हो गई है। 2015-16 और 2022-23 के बीच, 6.3 मिलियन अनौपचारिक उद्यम बंद हो गए, जिससे 16 मिलियन नौकरियां चली गईं। यह स्थिति श्रमिकों को गिग वर्क जैसे अस्थिर और असुरक्षित रोजगार की ओर धकेलती है।

गिग वर्कर्स को न केवल कम वेतन मिलता है, बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियां भी खराब होती हैं। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां डिलीवरी दरों में कटौती करती हैं, जिससे श्रमिकों की आय और घट जाती है। इसके अलावा, इन कंपनियों में डेटा गोपनीयता और अनुचित व्यापार प्रथाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए मज़बूत कानूनों की कमी है।

भारतीय सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, ने गिग वर्कर्स को मान्यता तो दी है, लेकिन कानूनी बाध्यताओं और सार्वभौमिक कवरेज की कमी के कारण इसे प्रभावी नहीं माना जाता। जबकि अमेरिका गिग वर्कर्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ब्राजील जैसे देश तेजी से उभर रहे हैं।

> गिग इकॉनमी भारत में रोजगार के नए अवसर तो ला रही है, लेकिन श्रमिकों के लिए असुरक्षा, कम वेतन और शोषण की समस्याएं भी खड़ी कर रही है। श्रमिक अधिकारों की रक्षा के बिना यह विकास टिकाऊ नहीं हो सकता।

भारत को गिग इकॉनमी की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और अन्य वैश्विक मंचों के साथ जुड़कर उचित वेतन और नौकरी प्रथाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

गिग इकॉनमी का अंधाधुंध विस्तार एक आधुनिक शोषण प्रणाली का रूप ले सकता है, जिससे असमानता बढ़ेगी और श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। भारत को श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मज़बूत कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए। इससे न केवल श्रमिकों का जीवन सुधरेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी दीर्घकालिक रूप से लाभान्वित होगी।

गिग इकॉनमी ने भारत में रोजगार के नए अवसर तो दिए हैं, लेकिन यह अवसर श्रमिकों के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आए हैं। जब तक सरकार और नीति निर्माता श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक गिग इकॉनमी असमानता और शोषण को बढ़ावा देने का जोखिम उठाती रहेगी। एक संतुलित और न्यायपूर्ण प्रणाली बनाने की दिशा में पहल करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक है।

महाकुंभ और भाजपा की चुनावी संभावनाएं

प्रो प्रदीप माथुर

संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले या ऐसा करने की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं को ही पता है कि महाकुंभ का उनके मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महाकुंभ का प्रभाव स्पष्ट है। महाकुंभ के बाद हमारे देश में राजनीति, खासकर सत्तारूढ़ भाजपा के बारे में, वैसी नहीं होगी जैसी पिछले महीने धूमधाम से शुरू हुए इस आयोजन से पहले थी।

महाकुंभ का महत्वपूर्ण महत्व यह है कि भाजपा ने चुनावों में अपने सबसे संभावित हथियार के रूप में हिंदुत्व को इसके स्थान पर लाने की कोशिश की है। इसका कारण हिंदुत्व कार्ड की कमजोर होती अपील है, जो पिछले साल लोकसभा चुनावों के बाद स्पष्ट हो गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखी है और पिछले हफ्ते दिल्ली के चुनावों में जीत हासिल की है। लेकिन यह मतदाताओं पर अपनी कमजोर होती पकड़ और संभावित खतरे के रूप में कांग्रेस के धीमे लेकिन स्थिर उदय के बारे में काफी सचेत है।

भाजपा की चुनावी रणनीति हमेशा भावनात्मक अपील और प्रभावी संचार अभियानों पर केंद्रित रही है, जिससे वह गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों को

> महाकुंभ भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा बना, लेकिन अव्यवस्था और भगदड़ ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया।

प्रमुख बनाकर अपनी कहानी गढ़ती रही है। हालांकि, अब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता जैसे वास्तविक मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने में सफलता पाई है। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि आजादी के बाद शुरू हुई लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। संविधान और डॉ. अंबेडकर के सम्मान पर विपक्ष के जोर ने भाजपा को चुनौती दी है, जबकि जाति जनगणना की मांग उसके पिछड़े वोट बैंक को प्रभावित कर रही है।

इसलिए, भाजपा के रणनीतिकारों को एक नए केंद्र बिंदु की आवश्यकता थी और उन्होंने महाकुंभ को उसकी परंपरा और इतिहास के साथ एक नए केंद्र के रूप में चुना। इसकी जड़ें सनातन हिंदू संस्कृति में हैं और यह जातिगत भेदभाव से परे बहुसंख्यक समुदाय को आकर्षित करता है। 144 वर्षों के बाद उभरने वाले जीवन भर के अवसर के रूप में घोषित करने के लिए ज्योतिषी थे और एक हिंदू ऋषि-सह-मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने मीडिया की मदद से इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। शीर्ष भाजपा नेताओं के बयानों के समर्थन से, महाकुंभ इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन लग रहा था। इसे एक नया मैच विनर माना जा रहा था।

रणनीति तो अच्छी थी, लेकिन चीजें वांछित दिशा में नहीं बढ़ीं। बयानबाजी तो अच्छी रही, लेकिन

अराजकता, लंबा ट्रैफिक जाम, आग लगने की घटनाएं, भगदड़ और आम तौर पर लोगों को परेशान करने की घटनाओं ने नए प्रतीक को नुकसान पहुंचाया। इसे भाजपा के शासन, कुशल प्रशासन और कुशल प्रबंधन के मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिशें भी सफल नहीं हुईं। 29 जनवरी की जानलेवा भगदड़ ने न केवल जानमाल का नुकसान किया, बल्कि भाजपा को असंवेदनशील नेताओं के समूह के रूप में भी पेश किया और इसकी सरकार ने वास्तविक मौतों के आंकड़ों को छिपाया और इस तरह पारदर्शिता की कमी की।

भगदड़ की घटना ने भले ही घिरे हुए शहर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में तीर्थयात्रियों के प्रवाह को सीमित नहीं किया हो, लेकिन इसने भाजपा नेतृत्व को गैर-भाजपा शासन के दौरान पहले के कुंभों को कमतर आंकने और 1954 के कुंभ भगदड़ के लिए कांग्रेस और उनके पसंदीदा लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने के अवसर से वंचित कर दिया।

29 जनवरी की भगदड़ ने भाजपा नेताओं के लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। परेशान आगंतुकों को मुस्लिम घरों और मस्जिदों में शरण मिली, जिनके दरवाजे तीर्थयात्रियों के लिए खोले गए थे। प्रयागराज के मुस्लिम निवासियों ने परेशान हिंदू तीर्थयात्रियों को भोजन और प्राथमिक उपचार प्रदान किया, और इन घटनाओं ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इसे प्रशंसात्मक शब्दों में रिपोर्ट किया। भाजपा को अल्पसंख्यकों से नफरत करने वाले अभियान से मिलने वाला चुनावी लाभ अब काफी कम होगा। कई नकली

महाकुंभ की भीड़ भाजपा के लिए समर्थन में नहीं बदली, चुनावी असर अनिश्चित बना हुआ है।

साधुओं और आवारा तत्वों द्वारा बहुत सारी गंदी हरकतें करने के कारण, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की लोकप्रिय छवि को शायद ही कोई लाभ हुआ हो।

आखिरी बात, महाकुंभ ने एक बार फिर दिखा दिया कि भाजपा गरीबों की बात करती है, लेकिन अमीरों की सेवा करती है। वीआईपी लोगों के लिए बिछाई गई लाल कालीन व्यवस्था ने आम लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतें पैदा कीं, जिससे यह बात साफ तौर पर जाहिर हुई।

हम इसे जिस भी तरह से देखें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2025 का महाकुंभ बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में है। हालाँकि 40 करोड़ लोगों का सरकारी आँकड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इस महीने के अंत में 45-दिवसीय कार्यक्रम के समापन तक लगभग 10 करोड़ लोग प्रयागराज आ चुके होंगे। कई और लोग वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं जा सके।

यह कहना मुश्किल है कि यह महाकुंभ मतदाताओं के मन पर क्या प्रभाव छोड़ता है। लेकिन एक बात निश्चितता के साथ कही जा सकती है कि महाकुंभ की ओर आकर्षित होने वाले सभी लोग भाजपा के समर्थक नहीं हैं। 1954 से ही कुंभ में भारी भीड़ उमड़ती रही है, लेकिन इससे जनसंघ-भाजपा की भगवा ब्रिगेड की चुनावी संभावनाओं को कोई मदद नहीं मिली। भाजपा नेतृत्व के बेहतरीन प्रयासों और मोदी-योगी जोड़ी की हार्दिक इच्छाओं के बावजूद 2025 का महाकुंभ ऐसा कर पाएगा या नहीं, यह बेहद अनिश्चित है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार , मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक हैं।

कांग्रेस फीनिक्स की तरह राख से उभर रही है।

आर के मिश्रा

जुनून और राजनीति में समय लगता है, निर्माण और खर्च दोनों में। और बुद्धिमान वह है जो अतीत के नमक से भविष्य को भरता है। आखिरकार, राख से फिर से जन्म लेने वाले फीनिक्स के लिए धूल को लुभाना कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए, उसे पहले जलना होगा।

28 दिसंबर, 1885 को बॉम्बे में 72 लोगों द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रक्रिया से कई बार गुज़रा है। नौ साल बाद, अपने 11वें अधिवेशन में, जब संख्या 1500 प्रतिनिधियों को पार कर गई, तो बहुत खुशी हुई। महात्मा गांधी द्वारा इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया गया, इसने स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया, इसे हासिल किया और 1977 तक देश पर शासन किया। जनता गठबंधन से पराजित होने के बाद, यह 1980 में सत्ता में वापस आया और 1989 तक शासन करता रहा, जब इसे एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने 1991 के साथ-साथ 2004 और 2009 में

> 1885 में बनी कांग्रेस कई बार बनी-बिगड़ी, लेकिन इसकी ऐतिहासिक छाप को मिटाना आसान नहीं। क्या राहुल गांधी की नई रणनीति पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएगी?

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा 2014 में सत्ता में आई और अपने तीसरे कार्यकाल में है। तब से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य पर 140 साल पुरानी कांग्रेस की ऐतिहासिक छाप इतनी व्यापक है कि उसे इतने कम समय में खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए कितना भी प्रयास क्यों न करना पड़े।

तीन निगलने से गर्मी नहीं आती। फिर भी, अभी के लिए, मीडिया के मसीहाओं ने अपना स्पष्ट फैसला सुनाया है। कांग्रेस फिर से गंभीर देखभाल की ओर बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से जीतना एक बार का आश्चर्य था। हरियाणा और दिल्ली राज्य विधानसभा चुनावों ने इसे संदेह से परे साबित कर दिया है। 28-पार्टी विपक्षी समूह, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) खस्ताहाल है, और राहुल गांधी का दोनों का नेतृत्व कहीं नहीं जाने वाला है। कुल मिलाकर, विपक्ष एक टोकरी का मामला है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अपने सर्वेक्षणों का स्वामी और स्वामी है।

इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मधुर प्रेमालाप के

लिए तैयार किए गए ढोल से करें, जो लगातार बढ़ते अपमानों की अनदेखी करते हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा के इर्द-गिर्द प्रचार की धूम 'खुशियों के दिन फिर से आ गए' की दोहराई गई कल्पना को तोड़ देती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को रियायतों के साथ पहले ही रोक दिया जाता है, जबकि अवैध अप्रवासी जंजीरों में जकड़े अपने वतन लौट जाते हैं।

भारत ने अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की पर शुल्क घटा दिया है, और ट्रंप ने उदारतापूर्वक उसे F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की है, जिसे एलन मस्क ने कभी "ड्रोन के युग में अप्रचलित" बताया था। मस्क अब ट्रंप प्रशासन का हिस्सा हैं।

गाजर भले ही छड़ी से बहुत छोटी हो, लेकिन इसका स्वाद मीठा होता है, जबकि चाबुक भयानक रूप से चौंकाता है। क्या यह मीडिया के एक के प्रति उत्कट प्रेम और दूसरे के प्रति अव्यक्त शत्रुता का कारण है, यह व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ देना ही बेहतर है।

हालांकि, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस के लिए प्रलय की भविष्यवाणियां प्रचलित रही हैं। इसकी शुरुआत 1962 के चीनी आक्रमण के बाद उनकी शासन करने की क्षमता पर सवाल उठाने वाली चिंता से हुई थी, "नेहरू के बाद कौन?"। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को शुरू में उनकी विनम्रता के लिए मज़ाक उड़ाया गया था, लेकिन वे दुनिया को राष्ट्रीय

कांग्रेस कभी देश की एकमात्र सत्ताधारी पार्टी थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने नया राजनीतिक संतुलन स्थापित कर दिया। क्या कांग्रेस खुद को पुनर्जीवित कर पाएगी?

सम्मान से भरकर चले गए और अपनी शारीरिक बनावट से कहीं ज़्यादा लंबे हो गए। उनके बाद सत्ता में आईं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 'गूंगी-गुड़िया' (गूंगी गुड़िया) होने के उपहास के साथ की और अंत में अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को धूल चटा दी, जबकि पाकिस्तान को विभाजित किया, रिचर्ड निक्सन प्रेसीडेंसी में अमेरिकी सातवें बेड़े और मजबूत हथियारों वाले अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को निशाने पर लिया।

कांग्रेस ने अपने नाम बदल दिए - कांग्रेस (आई) - कांग्रेस (आर) - क्योंकि उसने पार्टी में युवा खून भरने के लिए पुराने नेताओं को बेरहमी से हटा दिया। आज के कई दिग्गज नेता उनके समय के राजनीतिक नौसिखिए थे। राजीव गांधी, जो अपनी मां के उत्तराधिकारी बने, को भी इसी तरह निशाना बनाया गया, लेकिन दूरसंचार क्रांति और पंचायती राज को बढ़ावा देना उनके शासन की कई प्रमुख विशेषताओं में से कुछ हैं। भारतीय राजनीति की विडंबना यह है कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दो प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी देने वाले परिवार के बेटे पर देशद्रोह के अलावा कई मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मौजूदा सत्ता संरचना में बैठे लोग कहीं ज़्यादा भड़काऊ और मानहानिकारक भाषणों और कार्रवाइयों से बच निकलते हैं।

कांग्रेस का पतन मुख्य रूप से नरेंद्र

मोदी से उभर रहे खतरे का आकलन करने में विफल रहने के कारण हुआ, खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पदभार संभालने के बाद। उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अपनी पहली बैठक में ही अपनी योजनाओं से अवगत करा दिया था, जब उन्होंने कहा था, "मैं यहां पांच दिवसीय टेस्ट मैच खेलने नहीं आया हूं।"

पहले दिन से ही उन्होंने कांग्रेस शासित केंद्र के साथ टकराव मोल ले लिया, यह दलील देते हुए कि वह गुजरात को निशाना बना रहा है और उसे बदनाम कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे लेकर आज विपक्ष शासित राज्य खुद को खरी-खोटी सुना रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात के चालाक राजनेता द्वारा तय किए गए मैदान पर खेलने की रणनीतिक भूल की। वह अलग-अलग टिप्पणियों को उठाते, उन्हें गढ़ते और फिर उनका जवाब देते, इस तरह कहानी को गढ़ते। उन्होंने ऐतिहासिक समानताएं भी जोड़ीं कि कैसे नेहरू ने धरती के बेटे वल्लभभाई पटेल के साथ अन्याय किया और परिवार बस उसी परंपरा को जारी रखे हुए है। इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया कि स्वर्गीय इंदुलाल याग्निक, जिन्होंने महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया और गुजरातियों के लिए एक मातृभूमि के लिए नेहरू की ताकत को भी चुनौती दी, को 1960 में गुजरात के अस्तित्व में आने के बाद क्यों भुला दिया गया। यह राजनीतिक रूप से उचित नहीं था।

भाजपा कांग्रेस की पुरानी गलतियों को दोहराती दिख रही है, जबकि कांग्रेस गांधीवादी मूल्यों की ओर लौट रही है। क्या यह बदलाव भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगा?

कांग्रेस के भीतर निहित स्वार्थी तत्वों ने न केवल याग्निक को खारिज करने में बल्कि लड़खड़ाती कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने में भी बहुत कुछ किया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण राहुल गांधी का फरवरी 2014 में गुजरात में युवा कांग्रेस द्वारा 'विकास खोज' यात्रा का विचार था। यह एक शानदार सफलता थी और सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। इसके बाद युवा विंग के सदस्यता अभियान ने बड़े पैमाने पर फर्जी सदस्यता रद्द की और पार्टी में युवाओं का जोश भर दिया। हालांकि, पुराने नेताओं ने युवाओं के इस कदम को विफल कर दिया, जो अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है।

एक समय के भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला, जिन्होंने 1995 में केशुभाई पटेल सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, पार्टी को विभाजित किया था और कांग्रेस के समर्थन से गुजरात में सत्ता में आने के लिए अपना क्षेत्रीय दल बनाया था, के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वाघेला बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी बढ़ती हताशा के उदाहरण दिए क्योंकि पुराने कांग्रेसियों ने उनके लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। 'शक्ति-दल', जिसे उन्होंने भाजपा के बजरंग दल के प्रभावी प्रतिपक्ष के रूप में सफलतापूर्वक बनाया था, को कांग्रेस के पुराने नेताओं के

दबाव में भंग करना पड़ा। उनके अनुसार, सेवा दल इतना दब्बू और कमजोर था कि वह इतनी मजबूत ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। वाघेला ने शक्ति दल की 'ताकत' का प्रदर्शन तब किया था जब उन्होंने उत्तर गुजरात के राधनपुर से उपचुनाव लड़ा था, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के भीतर निर्वाचित होना था। मोदी उस समय भाजपा उम्मीदवार के चुनाव प्रभारी थे। कांग्रेस को उसकी गांधीवादी जड़ों की ओर वापस ले जाने की राहुल गांधी की रणनीति, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की राजनीति से अलग है, सही दिशा में उठाया गया कदम है। मतदाता आबादी के पास अब दो अलग-अलग राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं के बीच एक स्पष्ट विकल्प है। दूसरे, कम इस्तेमाल की जाने वाली राह पर चलने के फैसले ने लोगों को खुद चीजों को खुद देखने का मौका दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे, जिसके चलते भाजपा सरकार अब क्षेत्रीय बैसाखी पर है, इस बात का सबूत है कि वह सही रास्ते पर है। जरूरत है कि उनकी दादी की तरह पुराने नेताओं को रास्ते से हटाने की निर्ममता हो और खाली जगह को भरने के लिए ऊर्जावान युवा कैडर हो। मोदी को केवल कठोर जमीनी काम के जरिए ही मात दी जा सकती है। भाजपा पुरानी कांग्रेस की बुराइयों को तेजी से आत्मसात कर रही है; अब समय आ गया है कि प्राकृतिक

140 सालों में कांग्रेस ने उतार-चढ़ाव देखे, नेताओं को खोया, फिर बनी-बिगड़ी। लेकिन क्या 2024 के नतीजे इसके पुनरुत्थान की शुरुआत हैं?

आधारभूत बुद्धिमत्ता के साथ एक नई भविष्योन्मुखी कांग्रेस का निर्माण किया जाए। फिलहाल, कांग्रेस एक सक्षम राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है। भाजपा में जो लोग उनका और कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें 1984 के लोकसभा चुनावों की अपनी खस्ताहालत को याद करना चाहिए, जब वे दो सीटों वाली पार्टी में सिमट कर रह गए थे। गुजरात के मेहसाणा से एके पटेल और आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से सी जंगा रेड्डी। कांग्रेस, अपने सबसे खराब दौर में भी, 2014 में लोकसभा में 44 सीटें ही जीत पाई थी। इसके अलावा, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा का पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, फिर 1998-1999 में 13 महीने, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूरा कार्यकाल कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा बेदखल किए जाने से पहले चला। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में अपने तीसरे कार्यकाल में है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, उसे अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है।

जैसा कि पुरानी कहावत है, 'जन्म, पुनर्जन्म, जैसे प्रतीक्षा करने वाले मर जाते हैं। पुराने प्यार में, नए प्यार में उड़ने के लिए पंख उग आते हैं।

****

लेखक गांधीनगर स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं जो टीओआई, पायनियर और अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं

पूर्व बीजेपी मंत्री का सावरकर, हिंदुत्व पर प्रहार

हमारे संवाददाता द्वारा

वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी द्वारा लिखी गई हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर एक नई किताब ने भारत के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस किताब में उस व्यक्ति की विचारधारा को उजागर किया गया है, जिसकी यादों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार फिर से ताजा कर रही है। महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश में भाजपा बेशर्मी से लंबे समय से भुलाए गए सावरकर को फिर से जीवित कर रही है।

हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक "द न्यू आइकॉन: सावरकर एंड द फैक्ट्स" में 84 वर्षीय शौरी ने सावरकर द्वारा लिखे गए दस्तावेजों के साथ-साथ ब्रिटिश अभिलेखागार और साहित्य की मदद से सावरकर के काम और चरित्र की बारीकी से समीक्षा की है। शौरी ने सावरकर की संदिग्ध विरासत पर नई रोशनी डाली है और हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाने पर जोर दिया है।

अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी भाजपा नीत एनडीए सरकार में मंत्री रहे शौरी एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में विवरणों का बारीकी से अध्ययन करने और ऐसी बातें उजागर करने के लिए जाने जाते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले वे तथ्यों तक पहुँचते हैं। हालाँकि वे पहले भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन शौरी देश में व्याप्त वर्तमान स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान हैं, जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है।

> *द न्यू आइकॉन: सावरकर एंड द फैक्ट्स"* में अरुण शौरी ने सावरकर की विचारधारा और उनके ऐतिहासिक सच का खुलासा किया है। यह किताब गांधी बनाम सावरकर की राजनीति पर नई रोशनी डालती है।

क्या सावरकर और गांधी लंदन में "दोस्तों की तरह" साथ रहे, जैसा कि सावरकर ने गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान दावा किया था? क्या अंडमान में जेलरों की क्रूरता के कारण वे मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे? अंग्रेजों को उनकी दया याचिकाओं का क्या मतलब निकाला जाए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्या सावरकर ने अंग्रेजों को पूरे दिल से सहयोग देने का वादा किया था? क्या सावरकर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वह रास्ता दिखाया था जिस पर नेताजी ने बाद में चलना शुरू किया?

अपनी पुस्तक में शौरी ने इन और अन्य सवालों के जवाब देने के लिए

सावरकर की पुस्तकों, निबंधों, भाषणों, बयानों का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अभिलेखों को खंगाला है और पाठकों को समकालीन अभिलेखों के माध्यम से चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। उन्होंने जांच की है कि कैसे गांधी को मिटाने के लिए आज सावरकर को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिनके व्यक्तित्व ने हिंदुत्व के समर्थकों के लिए असुविधा पैदा की है।

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने शौरी का एक लंबा इंटरव्यू लिया है और इसे अपने चैनल पर प्रसारित किया है, जिसमें उसके संवाददाता जुगल पुरोहित ने मशहूर लेखक से खास बातचीत की है।

31 जनवरी को किताब के विमोचन के बाद सावरकर के प्रशंसक भड़के हुए हैं, क्योंकि द न्यू आइकॉन ने इस बात को पुख्ता तौर पर दर्शाया है कि गांधी की हत्या सावरकर की विचारधारा के मूल से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।

जबकि सावरकर के अनुयायियों ने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में मिथकों का ढेर लगा दिया है, शौरी ने कहा कि सावरकर अंग्रेजों से लड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, सिवाय इसके कि जब वे बहुत छोटे थे, तब उन्होंने हत्याओं और हिंसा की वकालत की थी। बाद में, उन्होंने अंग्रेजों से वादा किया और अपनी दया याचिकाओं में कहा: "मैं आपके लिए उपयोगी होऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका

अरुण शौरी की "द न्यू आइकॉन" सावरकर की विरासत, उनकी विचारधारा और ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करती है, जो आज की राजनीति के लिए बेहद प्रासंगिक

आभारी रहूंगा, कोई भी मेरे जितना राजनीतिक रूप से आपके लिए उपयोगी नहीं होगा ..."

सावरकर के इर्द-गिर्द फैली मिथकों को खारिज करते हुए शौरी ने कहा कि अगर भारतीय उन सूत्रों का पालन करें जो सावरकर ने हिंदू राष्ट्र के भारतीय राज्य के गठन के लिए निर्धारित किए थे, तो यह एक भगवा राज्य बन जाएगा जिसमें सुपर चालाकी, सुपर छल होगा, जिसका उन्होंने प्रचार किया और कहा कि हिंदुओं को इसे हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, "आखिरी पन्ने पर मैंने अपनी दलील दी है: हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाओ।"

शौरी ने कहा कि उनकी किताब में करीब 600 संदर्भ हैं, जो इसे सावरकर के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक प्रामाणिक ग्रंथ बनाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि सावरकर जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उनका मानना था कि मुसलमानों को भारत में रहना चाहिए लेकिन दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में। "मुझे इस सरकार से पहले कोई और सरकार याद नहीं है जिसने सावरकर के विचारों का आह्वान किया हो। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, इंदिरा गांधी के समय में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था और वाजपेयी के समय में संसद में एक चित्र का अनावरण किया गया था, लेकिन उनके विचार नहीं थे।

****

केजरीवाल की राह पर चलते प्रशांत किशोर

~ प्रो. हेमंत कुमार सिंह"

अरविंद केजरीवाल की "वैकल्पिक राजनीति" का हश्र प्रशांत किशोर देख रहे होंगे जो आजकल बिहार में तंबू टांग कर नई पीढ़ी को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे हाल फिलहाल तक अपने "जन सुराज" और अनशन को लेकर मीडिया में बहुत चर्चा पाते रहे थे। फिर, नित नई खबरों के रेले में कहीं गुम से हो गए हैं।

वे रणनीतियां बनाने में माहिर बताए जाते हैं इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे फिर कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जिससे उन्हें मीडिया अटेंशन मिलने लगे। वैसे भी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और प्रशांत किशोर इसमें अपनी भूमिका तलाशने वाले हैं।

अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, छा भी गए, दस साल मुख्यमंत्री भी रह लिए लेकिन आज तक उनसे यह सवाल अनुत्तरित ही रहा कि "पार्टनर, आखिर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?"

भले ही उन्हें भाजपा से महज दो तीन प्रतिशत कम, लगभग 43 प्रतिशत वोट मिले लेकिन जिन कारणों से वे पराजित हुए हैं वे दोबारा उन्हें उबरने देंगे इसमें गहरे संदेह हैं।

> अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिना किसी स्पष्ट वैचारिक आधार के टिक नहीं पाई, और उनके पराभव पर भाजपा विरोधी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।

बिना किसी स्पष्ट वैचारिक आधार के "सब चोर हैं जी"...और..."सब मिले हुए हैं जी" जैसी बातें पब्लिक के बीच उछाल कर केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह तो बना ली लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नया नहीं था जो उन्हें प्रासंगिक बनाए रख सकता था।

जहां विचारधारा की अनुपस्थिति है वहां मूल्य पनप नहीं सकते। यही कारण है कि अन्ना आंदोलन के अति उत्साह से निकला कोई राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल की जेबी पार्टी बन कर रह गया जिसमें असहमतियों का कोई स्थान नहीं था, जिसके कोई राजनीतिक मूल्य नहीं थे।

आम आदमी पार्टी कभी आरोपों के इस साये से बाहर नहीं निकल सकी कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आनुषंगिक उपकरणों की एक कड़ी मात्र है। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी, जो भाजपा के घोर विरोधी हैं, आज केजरीवाल के पराभव से खुश हैं।

विपक्षी दलों का गठबंधन, जो "इंडिया गठबंधन" कहा जा रहा है, महज एक राजनीतिक गठबंधन ही नहीं बल्कि एक वैचारिकी का प्रवक्ता भी है। यह वैचारिकी भाजपा के राजनीतिक सिद्धांतों के

स्पष्ट विरोध में खड़ी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करने की सोच रखने वाले नेताओं की समझ की बलिहारी है कि आखिर वे समझ क्या रहे थे। अगर केजरीवाल आगे भी इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हैं, जिसकी कि पूरी संभावना है, तो यह सवाल आगे भी पूछा जाता रहेगा।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो तब भी अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि के साथ राजनीति के मैदान में उतरी थी। खुद केजरीवाल भी सामाजिक कार्यों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त एक समर्पित और ईमानदार समाजसेवी की छवि के साथ अपनी पार्टी के नेतृत्व की भूमिका में आए थे।

प्रशांत किशोर तो खुद अपने अन्ना हैं और खुद ही केजरीवाल भी है। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, गांव गांव पदयात्राएं की, उसके बाद छात्रों के एक आंदोलन में शामिल हुए। खूब मीडिया कवरेज मिला। लोगों के बीच चर्चा भी हुई। उनके अनशन को लेकर उनके समर्थकों ने स्लोगन दिया "बिहार की ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ प्रशांत किशोर का आमरण अनशन।"

ठीक है कि आमरण अनशन को खत्म होना ही चाहिए था क्योंकि

बिहार में प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन उनकी शिक्षा सुधार की लड़ाई अब पीछे छूट गई दिखती है।

स्वस्थ प्रशांत किशोर बिहार के अधिक काम आ सकते हैं। लेकिन, सवाल यह है कि बिहार की जिस "ध्वस्त शिक्षा" की बात वे कर रहे थे उस मुद्दे पर बीते एक महीने से उन्होंने क्या किया है। पटना में एक तंबू नगर स्थापित कर लोगों को सत्याग्रह का प्रशिक्षण देते वक्त वे क्या बता रहे हैं लोगों को?

बिहार की ध्वस्त शिक्षा पर तो सवाल उठाने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। प्रशांत किशोर ने अगर यह सवाल उठाया था तो इतने दिन बीतने के बाद भी उन्होंने अब तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की जिसमें बिहार की शिक्षा के ध्वस्त होने के कारणों और जिम्मेदार लोगों की बातें होती?

बिहार की नई पीढ़ी की नसों में बिहार की भ्रष्ट और ध्वस्त शैक्षणिक संरचना रोज जहर के इंजेक्शन डाल रही है और प्रति वर्ष हजारों की संख्या में अकादमिक रूप से पंगु नौजवान डिग्रियां लेकर सड़क पर आ रहे हैं।

जिस राज्य के विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े संस्थानों के शीर्ष भ्रष्ट और पतित बुद्धिजीवियों की जमात से घिर गए हों, जहां के अधिकतर संस्थानों में संगठित लूट के सिवा और कुछ भी नहीं हो रहा हो, वहां शिक्षा का ध्वस्त होना और परीक्षा का मजाक बनना स्वाभाविक है। इनसे निकले नौजवान कौन सी दृष्टि, कैसी पृष्ठभूमि के साथ रोजगार के बाजार में उतरते होंगे?

बिहार के सामने हजारों दुश्वारियां हैं, न जाने कितनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार के विश्वविद्यालयों की दुर्दशा पर इतनी चुप्पी क्यों।

यह चुप्पी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है।

जब कोई सवाल नहीं उठा रहा था तब प्रशांत किशोर ने इन नपुंसक चुप्पियों के बीच बिहार की शिक्षा को विमर्शों के बीच लाया। फिर, वे भी चुप से हो गए। आजकल वे अपने साक्षात्कारों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता अधिक करते देखे सुने जाते हैं। उन्हें राजनीति करनी है तो वे बहुत सारी बातें एक साथ करेंगे ही। लेकिन, शिक्षा अब उनके एजेंडा में कहीं हाशिए पर चली गई है शायद। संभव है, सत्याग्रह प्रशिक्षण में वे अपने अनुयायियों के सामने इस विषयक कुछ प्रवचन देते हों।

प्रशांत किशोर ने जब जन सुराज की स्थापना की थी तब उनके मन में निश्चित ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदाहरण होगा। केजरीवाल की शोशेबाजियों ने तो तब भी कुछ मुकाम हासिल किया। काठ की हांडी एक बार तो अच्छे से रसोई पका ही देती है। लेकिन, उनकी विचारहीनता और मूल्यहीनता दोबारा उन्हें शायद ही अब उठने दे।

प्रशांत किशोर कोबिहार की ध्वस्त शिक्षा पर प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई थी, लेकिन अब वे भी अन्य

बिहार की ध्वस्त शिक्षा पर प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई थी, लेकिन अब वे भी अन्य मुद्दों में उलझ गए हैं, जिससे नई पीढ़ी निराश हो सकती है।

मुद्दों में उलझ गए हैं, जिससे नई पीढ़ी निराश हो सकती है। यह उदाहरण समझना होगा। उनकी विचारधारा का कोई स्पष्ट दृश्य सामने अभी तक नहीं आया है। लेकिन, उसकी एक झलक हाल में हुए बेलागंज विधानसभा उप चुनाव में दिखी। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उन्होंने वहां कहा, "सरकारी स्कूलों को तुरंत नहीं सुधारा जा सकता इसलिए हमारी जन सुराज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो गरीबों के बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करवाया जाएगा जिनकी फीस सरकार देगी।" क्या यही उनकी वैचारिकी है? यह तो नरेंद्र मोदी के नीति आयोग के उस सी ई ओ की उन बातों की याद दिला देता है जिसने आयोग की एक बैठक में कहा था, "सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और निर्धन बच्चों की फीस सरकार को भरनी चाहिए।" अगर यही प्रशांत किशोर का विजन है तो भगवान उनसे बिहार को बचाए।

बिहार दिल्ली नहीं है जिसने एक दौर में केजरीवाल को सिर पर उठा लिया था। वह दौर था और उस दौर की कुछ परिस्थितियां थी। प्रशांत किशोर के सामने वैसा राजनीतिक मैदान और वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। न वे स्वयं अब तक कुछ भी साबित कर सके हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए वे सवाल किसी बियाबान में गुम हैं। अगर इसी सवाल को वे मशाल बना लेते तो बिहार की नौजवान पीढ़ी उनमें कुछ उम्मीदें ढूंढती। पता नहीं, शायद वे अपने सत्याग्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस पर कुछ बातें कर रहे हों।

****

अमेरिका के विरुद्ध एकजुट होते पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश

डॉ. सलीम खान

नेतन्याहू की मौजूदगी में ट्रंप की दुर्भावनापूर्ण योजना मूलतः गाजा में उनकी संयुक्त हार की स्वीकृति है। इस योजना ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि तमाम तबाही के बावजूद गाजा पर जबरन कब्जा या इसके बहादुर लोगों को भागने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।

15 महीने के युद्ध में अपमानजनक हार के बाद वे अब पिछले दरवाजे से अपने इरादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह असफल रहेंगे। गाजा में हालिया युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। 24 नवंबर 2023 को एक अस्थायी युद्धविराम हुआ, लेकिन हमले फिर शुरू हो गए।

15 जनवरी 2025 को इजरायल और हमास के बीच दूसरा युद्धविराम समझौता हुआ, जो अब भी जारी है।

ट्रंप के प्रस्ताव ने अमेरिका के सहयोगी मिस्र को उलझन में डाल दिया। यहूदी मीडिया ने बताया कि इजरायल मिस्र के अल-अली बांध पर हमला कर सकता है, जिससे भारी बाढ़ आ सकती है और 1.7 से 10 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। मिस्र के सांसद मुस्तफा बाकरी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ, तो मिस्र के लोग अगले दिन तेल अवीव में होंगे। यह दिखाता है कि ट्रंप की गाजा पर कब्जे की योजना विफल हो गई है।

ट्रंप की गाजा विस्थापन योजना बुरी तरह विफल हुई। मिस्र और अरब देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेकर इसे खारिज कर दिया।

मिस्र और अन्य मुस्लिम देशों ने गाजा के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। 21 फरवरी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर, जॉर्डन और जीसीसी इस पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा के पुनर्निर्माण में 53 अरब डॉलर की जरूरत होगी, जिसमें पहले तीन साल में 20 अरब डॉलर खर्च होंगे।

मिस्र इस पुनर्निर्माण के दौरान शरणस्थल, मोबाइल घर और बंकर बनाएगा। इसके अलावा, रोजगार और नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मिस्र एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जो दशकों में फिलिस्तीन और अरब जगत के लिए सबसे प्रभावशाली साबित हो सकता है। यह सब ट्रंप के उस प्रस्ताव के जवाब में है जिसमें उन्होंने गाजा के

लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने और खाली जमीन अमेरिका को सौंपने की बात कही थी। इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनियों ने खारिज कर दिया, जबकि इजरायल ने समर्थन किया। इजरायल ने पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की, लेकिन इससे अमेरिका और इजरायल की और किरकिरी हुई। अगर वे फिलिस्तीन के इतिहास से परिचित होते, तो ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं रखते।

गाजा का इतिहास 5,000 साल पुराना है। 1949 से इस छोटे से क्षेत्र में 15 युद्ध हो चुके हैं। 1950 में मिस्र ने गाजा पर नियंत्रण किया, जबकि जॉर्डन ने वेस्ट बैंक संभाला। 1964 में फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं ने पीएलओ का गठन किया, और 1967 में इजरायल ने छह दिन के युद्ध में अरब गठबंधन को हरा दिया, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इजरायल ने 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा पर चार बड़े हमले किए, जिससे हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं थीं। इजरायल ने प्रतिबंधित फॉस्फोरस गैस का भी इस्तेमाल किया। हालिया युद्ध नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बढ़ाया।

2017 में ट्रंप ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, जिससे फिलिस्तीनी भड़क उठे। 2018 में इजरायल ने गाजा में एक गुप्त हमला किया, जिससे जवाबी कार्रवाई में हमास ने

गाजा ने 15 युद्ध झेले, लेकिन झुका नहीं। लाखों फिलिस्तीनी तबाही के बाद भी लौट आए, और ट्रंप की साजिश नाकाम हो गई।

एक इजरायली अधिकारी को मार दिया और सैकड़ों रॉकेट दागे। इजरायल मई 2021 तक खुद को रोक सका, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया, जिसके जवाब में हमास ने हजारों रॉकेट दागे। हमास अब केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि इजरायल पर हमले के लिए भी तैयार है। 2022 में फिलिस्तीनियों ने इजरायल में हमले किए, जिसमें 14 इजरायली मारे गए। जवाब में इजरायल ने "ब्रेक द वेव" सैन्य अभियान चलाया, जिसमें 146 फिलिस्तीनी मारे गए।

7 अक्टूबर 2023 के हमले को इसी ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह हमला बिना वजह नहीं था। इस बार हमास ने इजरायल में घुसकर एक सैन्य अड्डे पर हमला किया, जिससे 1,139 इजरायली मारे गए और 251 बंधक बना लिए गए। हमास की इस कार्रवाई ने इजरायल और उसके सहयोगियों को झकझोर दिया। 15 महीनों तक इजरायल ने गाजा में भारी विनाश किया, जिससे पुनर्निर्माण में 15 साल लगेंगे। लेकिन लाखों फिलिस्तीनी अपने बर्बाद घरों में लौट आए। ट्रंप ने इस दौरान फिलिस्तीनियों के विस्थापन की बात कही, लेकिन यह अब संभव नहीं। अगर ट्रंप फिलिस्तीनियों के इतिहास से परिचित होते, तो वे कभी ऐसी योजना का प्रस्ताव नहीं रखते, जिससे उन्हें वैश्विक अपमान सहना पड़ा।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

क्या महिलाओं के अधिकार और समाज में उनका स्थान गंभीर खतरे में है?

डॉ. सतीश मिश्रा

आज के इकोसिस्टम के नेताओं के कुछ बयान ध्यान देने लायक हैं। क्या वे 'महिला अधिकारों' के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं या नहीं?

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अधिक गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी समझ से, यह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो किसी की कृपा, दया या उदारता से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि विशेष रूप से समाज के बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या स्पष्ट रूप से कहें तो 'पुरुष वर्चस्ववादी' होने की पृष्ठभूमि में लंबे संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ है।

समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके बच्चे पैदा करने के अधिकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा निर्देशित बहस का सबसे अच्छा हिस्सा पूरी तरह से एकतरफा है, जिसमें केवल पुरुष ही समाज के सदस्यों से पूछे बिना ही आदेश जारी करते या हुक्म चलाते दिखते हैं, जो आज देश की आधी से अधिक आबादी का गठन करते हैं।

क्या आरएसएस और बीजेपी की जनसंख्या नीति महिलाओं के अधिकारों पर खतरा है? अरुंधति राय इस पर गहरी पड़ताल करती हैं।

देश में बहनों, माताओं और वयस्क महिला आबादी के साथ परामर्श का कोई संकेत नहीं है, जो कुल आबादी का आधे से अधिक हिस्सा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए, आइए पहले इस मुद्दे पर वास्तव में बोले गए शब्दों पर नज़र डालें।

इस वर्ष 25 जनवरी को, आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के मुख्य साधन-विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने "हिंदुओं में घटती जन्म दर" पर चिंता व्यक्त की और प्रत्येक हिंदू परिवार में कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आह्वान किया।

प्रयागराज में कुंभ के दौरान विराट संत सम्मेलन में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त करते हुए विहिप के केन्द्रीय महामंत्री बजंग लाल बांगड़ा ने कहा, "हिंदुओं की घटती जन्म दर के कारण देश में हिंदू आबादी में असंतुलन पैदा हो गया है। हिंदू समाज के पूज्य संतों ने प्रत्येक हिंदू परिवार में कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व हिन्दू परिषद के प्रयासों की सराहना करने वाले

पहले व्यक्ति थे, जिससे पता चलता है कि अधिक बच्चे पैदा करने के आह्वान को आधिकारिक संरक्षण भी प्राप्त है।

विहिप की यह अपील या कहें कि हिंदुओं के लिए यह एक आदेश है, जो अचानक या बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह एक सोची-समझी नीति का हिस्सा है, जो संघ-भाजपा की राजनीतिक रणनीति के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है, जिसके तहत हर मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम द्विभाजन के रूप में भुनाया जाता है, जो आम लोगों को गुमराह करने के प्रमुख तरीकों में से एक है, क्योंकि यह हिंदुत्व के "शत्रु सिंड्रोम" हथियार के साथ फिट बैठता है।

इससे पहले आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले साल 03 दिसंबर को दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने को कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय समाज जीवित रहे।

नागपुर में 'कथले कुल (वंश) सम्मेलन' में बोलते हुए, आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "कुटुंब" (परिवार) समाज का एक अभिन्न अंग है और हर परिवार एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि घटती जनसंख्या वृद्धि के कारण कई भाषाएँ और संस्कृतियाँ लुप्त हो गई हैं।

भागवत ने कहा, "आबादी में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है। लोकसंख्या शास्त्र (जनसांख्यिकी विज्ञान) बताता है कि जब किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से कम हो जाती है, तो उसके विलुप्त होने का खतरा होता है। इस गिरावट के लिए जरूरी नहीं कि बाहरी खतरे हों; समाज धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो सकता है।" "इस मुद्दे के कारण कई भाषाएँ और संस्कृतियाँ पहले ही लुप्त हो चुकी हैं। इसलिए, प्रजनन दर को 2.1 से ऊपर बनाए रखना आवश्यक है।"

हिंदुत्व की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और अधिकार— आरएसएस की जनसंख्या नीति पर अरुंधति राय का विश्लेषण।

यद्यपि भागवत ने देश की घटती जनसंख्या के बारे में बात की, लेकिन आरएसएस लगातार एक जनसंख्या नीति की वकालत करता रहा है, जिसका आधार यह विश्वास है कि हिंदू जनसंख्या अन्य समुदायों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों की तुलना में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है।

अक्टूबर 2022 में अपने वार्षिक विजयादशमी संबोधन के दौरान, भागवत ने कहा कि समुदायों के बीच जनसंख्या असंतुलन भौगोलिक सीमाओं को प्रभावित कर सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक समावेशी जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता पर बल दिया जिसका सभी सामाजिक क्षेत्रों को पालन करना चाहिए।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वैचारिक स्रोत आरएसएस ने 2015 में औपचारिक रूप से एक व्यापक जनसंख्या नीति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। तीन साल बाद, इसने सभी समुदायों पर लागू

जनसांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक समान कानून की वकालत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस साल 16 जनवरी को इस मुद्दे पर लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर किसी को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।

यह घटना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उस कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों बाद हुई है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। कहा जा रहा है कि अधिक बच्चे पैदा करने के नियम को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पर काम चल रहा है।

जैसा कि पहले ही संक्षेप में उल्लेख किया गया है, महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान, हरियाणा में 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' खोखला प्रतीत होता है और यह कहावत का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीत होता है कि "शिकार कुत्ते से करना और दौड़ खरगोश से करना"।

यह कहना न तो कोई शिष्टता है और न ही कोई रॉकेट साइंस कि एक बच्चे को जन्म देने और उसके प्रियजनों के पालन-पोषण का मुख्य भार निष्पक्ष लिंग पर होता है। जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चे के वयस्क होने तक, मुख्य रूप से महिलाओं पर ही इसका भार होता है। एक ओर, लैंगिक समानता का मुद्दा अभी भी एक जारी मिशन है क्योंकि कुछ कानूनी ढांचे के बावजूद इसे हासिल नहीं किया जा

बेटी बचाओ" या "बेटी बढ़ाओ"? आरएसएस के तीन बच्चों के आह्वान के पीछे की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण चर्चा।

सका है। मीडिया में हर दिन पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार की कहानियाँ सामने आती रहती हैं।

कई राज्य सरकारें, खास तौर पर भाजपा की सरकारें, 'नैतिक पुलिस' के तौर पर काम कर रही हैं। जाट समुदाय में खापें हैं जो 'प्रेम' के कारण विवाह को स्वीकार नहीं करतीं और प्रेम की सार्वभौमिक भावना के खिलाफ़ फरमान जारी करती हैं जो जाति, समुदाय और नस्ल की बाधाओं को स्वीकार नहीं करती।

लव जिहाद एक और हथियार है जिसका इस्तेमाल वयस्क लड़कियों को निजी संपत्ति के रूप में करने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने की प्रक्रिया में, राज्य के अधिकार क्षेत्र को बेडरूम तक बढ़ा दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को राज्य द्वारा स्वयं गंभीर जांच के अधीन किया जा रहा है जो निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है।

एक ओर, मोदी सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम पारित किया है, वहीं दूसरी ओर आरएसएस महिलाओं को पीछे धकेल रहा है, जिससे समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका खतरे में पड़ रही है।

दोहरे मापदण्ड का एक उत्कृष्ट उदाहरण!

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार, राजनैतिक विश्लेषक एवं मीडिया मैप के संयुक्त संपादक हैं।

महिला सशक्तिकरण: संघर्ष और सफलता

इंदु रानी सिंह

मार्च 8 एक ऐसा दिन है जिसे महिलाओं की पहचान बनाने का प्रयास कहा जा सकता है, एक ऐसा प्रयास जो सांस्कृतिक, नस्लीय, भाषाई, राष्ट्रीय, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में है, जो कि समाज को मजबूत करने के लिए समर्पण से भरी है, भावनाओ व मदद करने की उत्कृष्ट इच्छाशक्ति से पूर्ण है , जीवन भर पर्दे के पीछे रहकर परिवार की नींव रखने वाली है।

यह दिन लैंगिक समानता सशक्तिकरण के लिए चल रहे संघर्ष का परिणाम है। कानून ने अधिकार तो दिए हैं लेकिन समाज ने अभी तक उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। जैसे शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता, यौन हिंसा से मुक्ति, सार्वजनिक पद धारण करने में समान अधिकार, कानूनी अनुबंध और पारिवारिक कानून, काम करने का अधिकार और उचित मजदूरी और काम के बदले समान वेतन। संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 70 साल पहले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 में ही दे दिया था। लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख से पता चला कि अत्यधिक विकसित देश चीन में महिलाओं की स्थिति भारत से भी बदतर है। वहां युवाओं की संख्या में लगातार कमी आने के कारण देश के नेताओं ने आदेश दिया है कि कामकाजी महिलाएं अपनी नौकरी छोड़कर घर जाकर बच्चे पैदा करें। चीन में तीस साल से ऊपर की महिलाओं को 'शेंगनू' यानी बची हुई कहा जाता है। इसके बावजूद ये पढ़ी-लिखी महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वजह यह है कि काम करने के बाद भी बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। और भारत की तरह वहां भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 18 फीसदी कम वेतन मिलता है।

महिला दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि संघर्ष, समानता और सशक्तिकरण की पहचान है। समाज बदला तो है, लेकिन क्या महिलाओं को आज भी पूरा हक़ मिला?

कानून तो बने, पर असल बदलाव कब आएगा? समान वेतन, सम्मान और सुरक्षा के बिना क्या सच्ची बराबरी संभव है?

इन सबके बावजूद हाल के दिनों में सुनीता विलियम्स और रेखा गुप्ता दो ऐसी मिसालें हैं जो साबित करती हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं।

भारत में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समानता, यौन उत्पीड़न, उचित शिक्षा का अभाव

और घर संभालने की जिम्मेदारी जैसे कुछ मुद्दे बेहद ज्वलंत हैं,

महिला मतदाता बढ़ी, पर संसद में अब भी उनकी संख्या कम! क्या असली बदलाव तभी आएगा जब महिलाएं खुद फैसले लेंगी?

जिनका जिक्र आज बेहद जरूरी है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कुछ कानूनों को लागू करना भी जरूरी है, जैसे महिला सुरक्षा अधिनियम 1961, महिलाओं के अभद्र चित्रण पर रोक अधिनियम 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 498ए जिसे हाल के दिनों में काफी कमजोर कर दिया गया है, आदि।

यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1950 में ही मिल गया था, जबकि दुनिया के कई नामी देशों में महिलाओं को यह अधिकार आजादी के कई साल बाद मिला।

समस्या यह है कि चाहे कितने भी कानून बना दिए जाएं, जमीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं होगा जब तक कि उनके पास राजनीतिक ताकत न हो। यह भी एक कड़वा सच है कि भारत में अब महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है लेकिन संसद में महिलाओं की संख्या अभी भी सिर्फ 15 फीसदी है। पुरुष या तो महिलाओं को जीतने लायक नहीं समझते या फिर वे देश, कार्यस्थल और घर में महिलाओं की श्रेष्ठता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। पुरुषों की इस प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए दो हिंदी फिल्में 'अभिमान' और 'आंधी' काफी हैं।

स्वीडन, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका में संसद में महिलाओं की संख्या 45% है। मैक्सिको और रवांडा में तो यह संख्या 50% है। कोई भी समझ सकता है कि जिस देश में महिलाएं कानून बनाती हैं, वहां महिलाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी। एक और सच यह भी है कि दुनिया में जब भी महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह ब्रिटेन में मार्गरिट थैचर हों, श्रीलंका में श्रीमती भंडारनायके हों, इजरायल में गोल्डा मेयर हों, जर्मनी में एंजेला मार्कल हों या भारत में इंदिरा गांधी हों, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की धमकी की परवाह किए बिना बांग्लादेश को आजाद

चुनौती बड़ी है, लेकिन सुनीता विलियम्स और इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं साबित कर चुकी हैं—अगर मौका मिले, तो महिलाएं हर क्षेत्र में इतिहास रच सकती हैं!

कराया। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के लिए पंजाबी गाली का इस्तेमाल करते हुए अपनी किताब में इसका जिक्र किया था।

****

लेखिका एक गैर सरकारी संगठन प्रयास के कार्यकारी निदेशक हैं।

मार्च 23 : शहीद दिवस

उन क्रांतिवीरों की कुर्बानी जिनका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता

प्रशांत गौतम

मार्च 23, 1931 - यह तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है, लेकिन यह सुनहरी नहीं, बल्कि बलिदान की लाल स्याही से लिखी गई है। यह वही दिन है जब देश के तीन अमर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में देश की आज़ादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। यह सिर्फ तीन वीरों की शहादत की कहानी नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की एक ऐसी अमर गाथा है, जो हर भारतीय के रगों में देशभक्ति का खून दौड़ाने के लिए काफी है।

हालांकि, फांसी देने की आधिकारिक तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के गुस्से और संभावित विरोध को देखते हुए इसे 23 मार्च की शाम को ही गुपचुप तरीके से अंजाम दे दिया।

फांसी के बाद, जेल प्रशासन ने उनके शवों को चोरी-छिपे फिरोजपुर के सतलुज नदी किनारे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता को पता चलते ही भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी और शहीदों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई।

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कोई साधारण युवा नहीं थे। वे सिर्फ

20-23 साल के थे, लेकिन उनकी सोच और हिम्मत उम्र से कहीं आगे थी। बचपन से ही उन्होंने गुलामी की जंजीरों को महसूस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जब भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया, तो उन्होंने ठान लिया कि अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही होगी।

यह वह दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत क्रूरता की चरम सीमा पर थी। देशभक्तों को बेरहमी से कुचला जा रहा था। ऐसे में भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने खून से इंकलाब की आग जलाने की ठानी। उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सांडर्स को मारा, संसद में बम फेंका और अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर ललकारा।

क्या आज के युवा सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र में कोई अपनी जान हंसते-हंसते दे सकता है? उन्होंने जिंदगी जीने का सपना नहीं देखा, बल्कि भारत के भविष्य के लिए खुद को मिटा दिया। जेल में रहते हुए भी वे कमजोर नहीं पड़े। जब उनकी मां उनसे मिलने आईं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "मां, रोना मत, मैं भारत माता की गोद में सोने जा रहा हूं।" सोचिए, वो मां जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाया था, वो उस बेटे को खुद फांसी के तख्ते पर जाने के लिए तैयार होते देख रही थी! तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या हममें इतनी हिम्मत है?

जब आखिरी समय आया, तो तीनों वीर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर "इंकलाब जिंदाबाद" के नारे लगाते

हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। अंग्रेज भी उनकी हिम्मत देखकर कांप गए। उनकी आत्मा अमर हो गई, लेकिन क्या हम उनकी कुर्बानी का मोल समझ पाए?

लेकिन जिस भारत के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या आज वह भारत वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था? जवाब मिलेगा -"नहीं!" आज़ादी की लड़ाई हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन आज का भारत बंट चुका है। आज देश की सरकार खुद को मजबूत बनाने के लिए देश को कमज़ोर कर रही हैं।

आज का भारत दो बड़े संकटों से जूझ रहा है : राजनीतिक भ्रष्टाचार और समाज में बढ़ती नफरत।

1. देश की संपत्ति बेची जा रही है – सरकारी कंपनियां, रेलवे, एयरपोर्ट, शिक्षा , बैंक और प्राकृतिक संसाधन धीरे-धीरे निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। क्या भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए जान दी थी, जहां आम आदमी का हक कुछ उद्योगपतियों के पास चला जाए?

2. हिंदू-मुस्लिम, जातिवाद और दंगे – अंग्रेजों ने (Divide and Rule) की नीति अपनाई थी, लेकिन क्या हम आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं? धर्म और जाति के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है, और हम लड़ भी रहे हैं! क्या आज़ादी की लड़ाई किसी एक धर्म ने लड़ी थी? नहीं! हर धर्म और हर जाति ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर आज क्यों हम अपने ही भाइयों के खिलाफ हो गए हैं?

3. युवा दिशाहीन हो गया है – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए मरने को तैयार थे, और आज का युवा? सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, धार्मिक उन्माद, जातीय घृणा में उलझा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन युवा इन मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठा रहा। उसे असली दुश्मन नहीं दिखता, बल्कि वह वही नफरत फैलाने वालों का शिकार हो गया है।

शहीदों ने आज़ादी दिलाई, पर क्या हमने उनके सपनों का भारत बनाया? या नफरत और भ्रष्टाचार ने हमें भटका दिया?

आज हम सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, छोटी-छोटी परेशानियों पर टूट जाते हैं, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा भारत के लिए समर्पित कर दिया। अगर वे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, तो क्या हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहेंगे या देश के लिए कुछ करने का प्रण लेंगे?

शहीदों का सपना था कि भारत एक समृद्ध, स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र बने। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें। वे जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा हर देशभक्त के दिल में बसती है। उनके विचारों को अपनाइए, उनकी क्रांति को आगे बढ़ाइए और अपने अंदर देशभक्ति की वह ज्वाला जलाइए, जो कभी न बुझे।

हमे अब क्या करना चाहिए?

- नफरत और झूठी राजनीति का शिकार मत बनो।

- अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ—शिक्षा, रोजगार, समाजसेवा और जागरूकता में।

- नेताओं की चाल को समझो, उनका अंध समर्थन मत करो।

- देश के संसाधनों पर नजर रखो, उन्हें बेचने मत दो।

- जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचो, क्योंकि आज़ादी सभी ने मिलकर हासिल की थी।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-कातिल में है।"

जय हिंद! वंदे मातरम्!

****

लेखक मीडिया मैप के मुख्य सह - सम्पादक हैं।

अनूप श्रीवास्तव श्रद्धांजलि सभा

अंकुर कुमार

नई दिल्ली: दिनांक 22.02.2025 (शनिवार) को प्रातः 11.30 बजे से अट्टहास पत्रिका के प्रमुख संपादक स्व. अनूप श्रीवास्तव की स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष और सुविख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा ने की। अनूप श्रीवास्तव के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की।

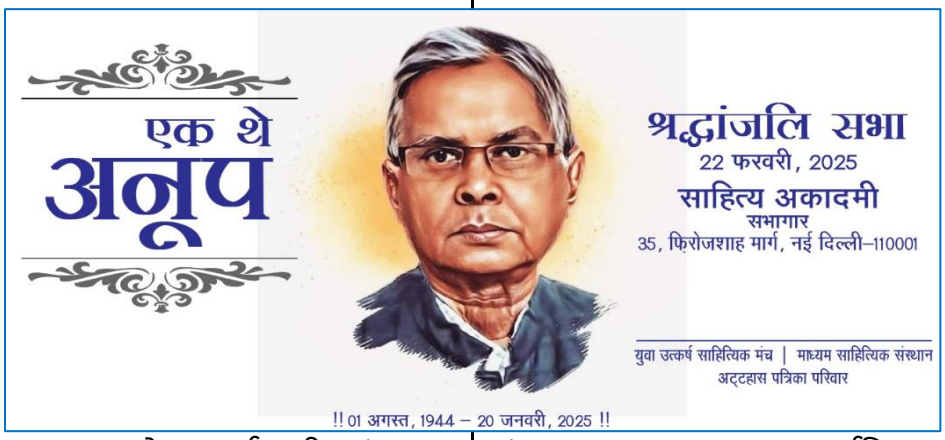

अट्टहास के कार्यकारी संपादक रामकिशोर उपाध्याय ने अनूप श्रीवास्तव के व्यक्तित्व के विविध साहित्यिक पहलुओं की संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि अपने स्वयं के महत्वपूर्ण कविता और व्यंग्य लेखन के अतिरिक्त गत चालीस वर्षों से व्यंग्य लेखन हेतु अट्टहास शिखर और युवा पुरस्कार दिया जाना और पच्चीस वर्षों से अट्टहास का निर्बाध मासिक प्रकाशन अनूप श्रीवास्तव जी की दो व्यक्तिगत महान उपलब्धियां हैं, जिनके कारण हास्य/ व्यंग्य हिंदी साहित्य में चर्चा और लेखन का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

पूर्ण गरिमा के साथ लंबी चली इस सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने-अपने संबंधों के अनुरूप अपनी-अपनी शैली में अनूप श्रीवास्तव के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को साझा किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ व्यंग्यकार हरीश नवल, प्रेमजनमेजय, सुभाष चंदर, श्रवण कुमार उर्मलिया, रणविजय राव, राजेंद्र सहगल, एम.एम. चंद्रा, सुनील कुमार जैन राही, कथाकार बलराम अग्रवाल, डॉ. कीर्ति काले, गोपाल मिश्रा, अश्विनी कुमार, शैलेन्द्र कपिल, अंजू निगम, मेजर जनरल विनोद द्विवेदी, सूक्ष्म लता महाजन, राजेंद्र कुमार महाजन, विनय विक्रम 'मनकही', श्रीमती स्तुति कक्कड़, सुश्री पूनम झा, रंजना अग्रवाल, प्रदीप माथुर, मोहित सिन्हा, निशि मिश्रा, महेंद्र भीष्म, आलोक वर्मा, ओम प्रकाश शुक्ला, मोनालिसा मुखर्जी, अरविंद असर के अतिरिक्त अन्य कई साहित्यकार, उनके कई मित्र, निकट संबंधी और उनकी पुत्री शिल्पा श्रीवास्तव, दामाद सुधांशु माथुर, नाती अविका माथुर भी इस सभा में उपस्थित हुए।

अनूप श्रीवास्तव की सुपुत्री और अट्टहास की संपादक शिल्पा श्रीवास्तव ने कहा – अट्टहास का निरंतर संपादन और प्रकाशन पिता जी का जुनून था और अब हमें अट्टहास को निरंतर प्रकाशित करते रहना होगा।

सभा का संचालन श्री रामकिशोर उपाध्याय ने किया। साहित्यकारों से प्राप्त उनके शोक संदेश पढ़कर सुनाए गए, जिनमें माध्यम साहित्यिक संस्थान के अध्यक्ष कप्तान सिंह, अरुण अर्नव खरे, गिरीश पंकज उल्लेखनीय हैं। साथ ही, अरुण अर्नव खरे ने शांति गया साहित्य, कला और खेल संवर्धन मंच की ओर से अनूप श्रीवास्तव की स्मृति में व्यंग्य लेखन हेतु 11,000/- रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की सूचना दी गई।

अनूप जी के साहित्यिक अवदान का स्मरण करने के बाद अंत में उनकी आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

****

लेखक मीडिया मैप के सह - सम्पादक हैं।

कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण

मीडिया मैप नेटवर्क

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है; यह एक सामाजिक मुद्दा भी है जो कार्यस्थल संस्कृति की उत्पादकता और मानसिक भलाई को प्रभावित करता है।" यह विचार है अधिवक्ता सीमा जोशी के, जिनकी नई पुस्तक *ब्रेकिंग द साइलेंस: ए हैंडबुक ऑन पीओएसएच एक्ट* का विमोचन 14 फरवरी को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ।

पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली उच्च न्यायालय की वर्तमान न्यायाधीश प्रतिभा मनिंदर सिंह ने किया। पैनलिस्टों में आकाश एयर की गवर्नेंस और रणनीतिक अधिग्रहण प्रमुख प्रिया मेहरा, वरिष्ठ

बौद्धिक संपदा वकील स्वाति सुकुमार और अधिवक्ता जयंत बख्शी शामिल थे।

एक प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में अधिवक्ता सीमा जोशी को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों और प्रगति का अग्रिम ज्ञान है। वह चाहती हैं कि लोग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में बात करें, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और संगठनों व व्यक्तियों को सशक्त बनाएं। उनकी यह पुस्तक इन चर्चाओं को सबसे आगे लाने का लक्ष्य रखती है।

अपनी पुस्तक में उन्होंने न केवल पीओएसएच अधिनियम का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया है, बल्कि महत्वपूर्ण केस स्टडीज़ और ऐतिहासिक निर्णयों को भी शामिल किया है, जिन्होंने इसके कार्यान्वयन को आकार दिया है।

जोशी ने कहा, "इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य अंतराल को पाटना, कानूनी जटिलताओं को सरल बनाना तथा संगठनों, व्यक्तियों और कानूनी व्यवसायियों को कानून और उसके कार्यान्वयन की व्यापक समझ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।"

इस कार्यक्रम में चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं में से एक कार्यस्थल उत्पीड़न के बारे में चुप्पी तोड़ने और पीओएसएच अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

चर्चा के दौरान, अतिथियों ने पीओएसएच अधिनियम के कानूनी आधार, इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों, प्रभावशीलता और जागरूकता के बारे में बात की। बातचीत के दौरान प्रशिक्षण, आंतरिक समितियों, अंडर-रिपोर्टिंग, प्रतिशोध और झूठी शिकायतों से जुड़े सवाल भी उठे।

हालांकि कानून ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन पैनलिस्टों के बीच आम सहमति थी कि यह पर्याप्त नहीं है। यह भी कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है।

न्यायमूर्ति सिंह ने आईसीसी की कार्यप्रणाली में और अधिक लचीलेपन की मांग की तथा बताया कि समिति में कई सदस्यों - एक पीठासीन अधिकारी, दो कर्मचारी, एक एनजीओ का सदस्य - की आवश्यकता के कारण शिकायतों के निवारण में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा, "कभी-कभी आईसीसी की कार्यवाही पूरी होने में 8 या 9 साल लग जाते हैं, इसलिए आईसीसी की कार्यप्रणाली में अधिक लचीलापन होना चाहिए।"

कुछ केस स्टडीज़ पर चर्चा करते हुए पैनलिस्टों ने यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायतों के मुद्दे पर भी बात की। जयंत बख्शी के अनुसार, ऐसे मामलों की संख्या नगण्य है और वे आमतौर पर बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का नतीजा होते हैं। बख्शी ने कहा, "बहुत से लोग ऐसे हैं जो मामले की रिपोर्ट नहीं करते और जो करते हैं उनमें से 99.5% मामले वास्तविक होते हैं, केवल 1% या 1.5% मामले झूठे होते हैं।"

चर्चा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु पीओएसएच अधिनियम की लैंगिक प्रकृति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। जबकि कानून मुख्य रूप से महिलाओं के उत्पीड़न को संबोधित करता है, यह मान्यता बढ़ रही है कि पुरुष भी उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं।

बख्शी और सुकुमार ने प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया ताकि उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जा सके, तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पुरुष और महिला दोनों को उत्पीड़न महसूस होता है तो वे शिकायत दर्ज करा सकें।

प्रिया मेहरा ने कहा, "लिंग-तटस्थ नीतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मेरा मानना है कि सभी सहकर्मियों को यह महसूस होना महत्वपूर्ण है कि उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।"

****

एक दिव्य पुरुष

श्री दिनेश वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' में प्रकाशित हुई जो 27 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद "मेरे समय की मेरी कहानियाँ" के रूप में हुआ। प्रस्तुत कहानी उसी संग्रह से ली गयी है। - संपादक

****

जब प्रेमजी मेरे ऑफिस में मुझ से मिलने आए तो वह मुझे काफी दुर्बल और ढ़ीले ढाले लगे। यह मुझे बाद में पता चला कि वह कुछ दिन पहले ही गंभीर बीमारी को झेल कर आए थे। उन्हें नई दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था और वह भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि एक श्रीव्हीलर के ड्राइवर द्वारा। प्रेमजी ने पार्लियामेंट मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक से घर तक जाने के लिए श्रीव्हीलर किया था।

प्रेमजी को बस इतना याद था कि वह श्रीव्हीलर में बैठे थे और उन्होंने ब्रीफकेस खीच कर अपने करीब रख लिया था क्योंकि उसमें अच्छी खासी रकम थी जिसकी उन्हें उस समय बेहद आवश्यकता थी। एक लाल बत्ती पर श्रीव्हीलर को रुकना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं मालूम क्योंकि जब उनकी आँखे खुली तो उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए पाया जहाँ चारों तरफ सफेद वस्त्र पहने नर्से भाग दौड़ कर रही थी और कुछ डॉक्टर बीमारों का निरीक्षण कर रहे थे। जब वह कुछ समझ पाने की स्थिति में आए तो सब से पहले उन्होंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में अपना ब्रीफकेस माँगा जो उनके भाई ने उन्हें दे दिया। उन के भाई ने ही उन्हें आगे की कहानी भी बताई जो उन के भाई को श्रीव्हीलर के ड्राइवर ने सुनाई थी। वह श्रीव्हीलर का ड्राईवर ही था जिसने परिवार को सूचित किया और प्रेम के भाई को उसी ने ब्रीफकेस भी सौंपा। प्रेमजी ने कांपते हुए हाथों से ब्रीफकेस खोला और उसमें हर चीज़ को अपने स्थान पर पाकर चैन की साँस ली।

कहानी का बाकी हिस्सा प्रेमजी ने बड़ी भावुकता के साथ मुझे सुनाया। श्रीव्हीलर लाल बत्ती पर रुका लेकिन फिर स्टार्ट नहीं हुआ जबकि ड्राइवर ने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। ड्राइवर ने श्रीव्हीलर को सड़क के किनारे लगाया, अंगोछे से अपना पसीना पोछा और फिर श्रीव्हीलर को स्टार्ट करने के लिए उसके पास आकर खड़ा ही हुआ था कि उसकी नज़र उसमें बैठे यात्री पर पड़ी जो अब तक बिलकुल खामोश बैठा था। यह बात बड़ी अजीब सी लगी। इसलिए उसने यात्री को बड़े ध्यान से देखा। वह यात्री श्रीव्ह. ीलर में बड़े अजीब ढंग से बैठा हुआ था। उस के बैठने का ढंग स्वाभाविक नहीं था। वह समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। प्रेमजी सीट पर बेहोश पड़े थे और उनका ब्रीफकेस उनके बाईं तरफ अलग थलग पड़ा हुआ था। ड्राइवर उनकी हालत देख कर बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन डर कर उसने अपना मानसिक सन्तुलन नहीं खोया। आगे के कदम उसने बहुत समझदारी और सूझबूझ से उठाए।

उसने हिम्मत करके प्रेमजी को ज़ोर से झंझोरा कि शायद वह होश में आ जाएं। लेकिन जब वह टस से मस नहीं हुए तो उसने फिर श्रीव्हीलर के इंजन को जगाने की जम कर कोशिश की और भाग्य ने उस का साथ दिया। श्रीव्हीलर स्टार्ट हो गया। फिर क्या था। वह सीधा प्रेमजी को ले कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग पर पहुँचा और उन्हें वहाँ एडमिट करा दिया। वही बैठे बैठे उसने प्रेमजी का ब्रीफकेस खोला जिस में उसे पांच सौ के नोटों की गड्डीयों के बीच एक डायरी रखी मिली। डायरी में प्रेमजी के घर का पता लिखा था। सब कुछ वैसा

का वैसा ही छोड़कर, डायरी से उसने टेलीफोन नम्बर नोट किया और पास के बूथ में जाकर उनके घर पर टेलीफोन करके फिर वह बाहर आकर बैठ गया और प्रेमजी के घर वालों के आने का इंतज़ार करके लगा। इस बीच डॉक्टर जो उसे प्रेमजी का संबंधी समझ रहे थे उनकी सुधरती हुई दशा के बारे में बार बार आ कर बता देते थे। क्योंकि यह हादसा एक्सीडेंट का नहीं था इसलिए अस्पताल वालो ने पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं समझी।

कुछ देर बाद उसने कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा जो सीधे उसके पास ही आ रहे थे। ड्राइवर ने अपना परिचय देते हुए सारी कहानी विस्तार से बताई और ब्रीफकेस प्रेमजी के बड़े भाई को दे दिया जिसे दे कर उसे ऐसा लगा मानों किसी ने उसके सर से टनों का वजन हटा दिया हो। उस के अन्दाज़ से उस में कम से कम एक लाख रुपए तो अवश्य थे। प्रेम के घर वाले प्रेमजी की तरफ से इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने ड्राइवर से जल्दी जल्दी सारी बात सुनी, ब्रीफकेस लिया, और प्रेमजी के पास पहुँच गए।

प्रेमजी जो अब काफी हद तक ठीक थे उन्होंने ड्राइवर के बारे में पूछा जिसने उन्हें अस्पताल में न केवल एडमिट कराया बल्कि इतने ढंग से देखभाल की जैसे घर के सम् बन्धी या दोस्त करते हैं। वह उसे बुला कर उस का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते थे और जो कुछ बन पड़ता वह इनाम में देने को तत्पर थे। लेकिन प्रेम के भाई जब उसको बुलाने के लिए बाहर भागे तो वह वहाँ नहीं था। सब जगह छान मारा लेकिन उसका दूर दूर कुछ पता नहीं था। वह नेक बंदा बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से जा चुका था।

"मैं नहीं जनता कि मैं क्या कहूं।" प्रेमजी एक आह के साथ बोले। प्रेमजी भारत सरकार के वरिष्ट अधिकारी थे। लेकिन उससे पहले वह एक जाने माने कवि थे। और उनके हर कार्य में उनके संवेदनशील स्वभाव की झलक मिलती थी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने आंसू भरी आँखों से अपनी बीमारी की कहानी सुनाई। बस मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि वह किस बात को लेकर इतना दुखी थे, अपनी बीमारी को लेकर या ड्राईवर के बारे में सोच कर।

"मुझे औरों का तो नहीं पता लेकिन वह कोई देवता स्वरूप व्यक्ति था," उन्होंने आंसू भरी आँखों से कहा। "और कौन जानता है कि उन ड्राईवरों में से उस जैसे कितने हैं ले.ि कन, जैसे कि कहावत है 'एक गंदी मछली सारा तालाब को गन्दा करती है' इसी तरह कुछ गलत लोगों की वजह से अच्छे लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है।" यह कह के उन्होंने अपनी बात समाप्त की। साफ़ मालूम पड़ रहा था कि उन्हें इस बात का बहुत दुःख था के वह उस महान व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाए जिसके कारण उनको दूसरा जन्म मिला था।

प्रेमजी तो चले गए लेकिन मुझे ऐसी ही किस्से कहानियों के भवंर में छोड़ गए जो कभी न कभी मैंने जीवन में देखी और सुनी थी। जहा मुझे उन बहादुर लोगों के बारे में सोचकर फक्र होता है, चाहें वह पुलिस वाले हों या आम नागरिक, जो अपनी जान को ख़तरे में डाल कर दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए खतरनाक अपराधियो से भिड जाते है वहाँ मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो पाँच साल की लड़की को अपना शिकार बनाने में भी नहीं झिझकते है और अपाहिज लोगों को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। और ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। यूँ कहिए डकेतों के बीच में संत भी हैं और शहर और गाँवों में शराफत का मुखोटा पहने हुए दरिन्दे भी।

जितना मैंने विचार किया उतना ही मेरे दिमाग में यह बात बैठती गई कि जहाँ एक और बुराई और गिरावट की गहराई की सीमा नहीं है, वहीं दूसरी ओर, नेकी और भद्रता की बुलन्दी को नाप पाना भी संभव नहीं है। वह शिखर समस्त पृथ्वी पर अपनी सुखमय रौशनी फैला कर मानव जाति को अद्भुत सुख की अनुभूति प्रदान करता है।

****

अंदाज़-ए-लखनऊ

लखनऊ की विरासत गंभीर खतरे में?

डॉ सतीश मिश्रा

गंगा-जमुनी तहजीब मेरे शहर की जीवन रेखा की तरह काम करती है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे छात्र जीवन के दौरान मेरे मौलिक मूल्य निहित हैं - जिसे कैनिंग कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है।

मैंने शहर में जो कुछ सीखा और देखा, वह मुझे हिंदू-मुस्लिम नजरिए से देखने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा।

लखनऊ खास तौर पर और अवध आम तौर पर दो समुदायों के बीच परस्पर निर्भरता की कहानी रही है। शहर का जीवन और उसका व्यवसाय दोनों समुदायों के एक साथ काम करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

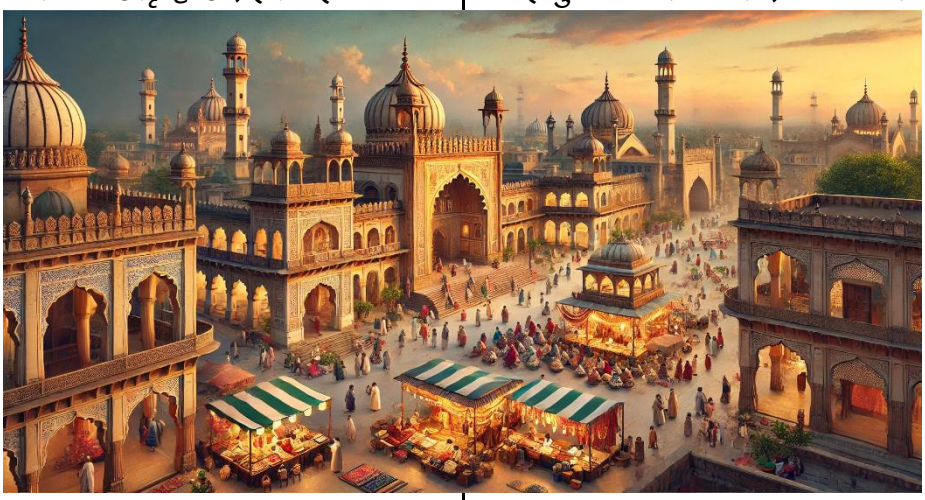

चाहे वह मशहूर चिकन का काम हो या लखनऊ का खाना, दोनों समुदाय मिलकर काम करते हैं ताकि आजीविका सुनिश्चित हो सके। जबकि अधिकांश कारीगर मुस्लिम हैं, जो चिकनकारी के जटिल उत्पाद बनाते हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है।

इसी तरह, कबाब, कोरमा या अन्य मांसाहारी व्यंजन सभी को पसंद आते हैं। इसी तरह, गिलोरी या रबड़ी जैसी

शहर की मिठाइयों का स्वाद सभी को पसंद आता है, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों या मानते हों।

लखनऊ की साहित्यिक परंपरा-उर्दू शायरी-हिंदी कविता या प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है क्योंकि यह आम संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है। शहर में मुशहरियों या कवि सम्मेलनों में हर कोई शामिल होता है जो अपने अनूठे तरीके से बारीकियों और समृद्ध कल्पना को समझते हैं। शहर की परंपरा का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि लेखक और इसके निर्माता समाज के हर वर्ग से आते हैं।

दोनों समुदायों के साझा प्रयासों से ही व्यापार फलता-फूलता है। यह कल्पना से परे है कि एक दूसरे के बिना जीवित रह सकता है।

मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि इन साझा मूल्यों को जनविरोधी ताकतों से गंभीर चुनौती मिल रही है। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर कैसे लड़ें, जिन्हें लंबे समय से विकसित हुई चीजों को नष्ट करने में कोई संकोच नहीं है। हमारी विरासत दांव पर है।

आइए हम इन ताकतों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हों और इनके भयावह इरादों को हराने के लिए एकजुट होकर काम करें।

****

चांदी की चप्पलें बनाने वाली लखनऊ की हुनरजादी

ज़ेबा हसन

चांदी के टुकड़े को आग के सामने पिघलाते हुए, चांदी के पत्ते को पीटकर आकार देते हुए या फिर घुंघरू और नगों को जड़ती हुई आफिया के हुनर को जो देखता है देखता ही रह जाता है-

रेड, महरून वेलवेट के ऊपर चांदी की नक्काशी के साथ घुंघरू और नंगों से जड़ी चांदी की जूती लखनवी दस्तकारी की खास पहचान है और इस हुनर की विरासत को संभाल रही हैं आफिया खान-

लखनऊ का चौक इलाका, जहां की तंग गलियों में हुनर का खजाना छिपा है। कहीं रेशम के धागों का जाल नजर आता है तो कहीं मुकैश वर्क की कारीगरी लोगों को हैरान कर देती है। यहां की महिलाओं ने लखनऊ की दस्तकारी को नए आयाम दिए हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे हुनर की जिसपर सिर्फ पुरुषवर्ग का कब्जा था लेकिन आफिया खान ने इस परम्परा को तोड़ते हुए एक नई इबारत लिखी है। यह हुनर है चांदी की चप्पल बनाने का। पूरे शहर में आफिया अकेली ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने पिता का पुश्तैनी काम को ना सिर्फ संभाला है बल्कि इस हुनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं।

दुलहन के लिए बनती है चांदी की चप्पल

नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदाज भी नवाबी है। फिर वह चाहे खाना हो या पहनावा। चांदी की जूती भी नवाबी दौर के पहनावे का एक खास हिस्सा हुआ करती थी। वह दौर तो खत्म हो गया लेकिन लखनऊ की नई दुलहन आज भी पांव में चांदी की चप्पल पहनकर अपनी ससुराल में कदम रखती है। यही वजह है कि सुनारों की दुकान पर सोने चांदी के अभूषणों के साथ चांदी की चप्पल भी शादी की शॉपिंग का हिस्सा होती हैं। चौक

इलाके से ताल्लुक रखने वाले हाफिज मोहम्मद अशफाक चांदी की चप्पलों के ऐसे कारीगर हैं जिनकी पुश्ते इसी काम को करती आ रही हैं। नौ भाईयों में सबसे छोटे हाफिज मोहम्मद अशफाक 1972 से अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं और अब उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं उनकी सबसे छोटी बेटी आफिया खान।

चांदी को गलाने से लेकर मार्केट तक का काम

आफिया सुबह सात बजे से अपने घर पर बनी वर्कशॉप पर काम शुरू कर देती हैं। चांदी के टुकड़े को हीट से गलाना, गलने के बाद पत्ते को पीट-पीट कर उसे आकार देना, घुंघरू और नग लगाना, सांचे पर कपड़े को पेस्ट करना सभी काम आफिया बखूबी करती है। आफिया कहती हैं कि अब्बा के साथ अब मैं मार्केट भी जाती हूं। चांदी खरीदना भी अब मुझे आ गया है। इन चप्पलों में हम प्योर और ठोस चांदी का इस्तेमाल करते हैं। सहालग के टाइम काम काफी ज्यादा होता है। शादीयों के सीजन में कई बार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक भी मैं काम करना पड़ता है। यह काफी नाजुक और मेहनत का काम है लेकिन मैं अपने इस काम को बहुत इंजाय करती हूं। आफिया कहती हैं कि हमारा पुशतैनी मकान चौक में हैं लेकिन अब हम लोग राजाजी पुरम में रहते हैं और यहीं हमारी वर्कशॉप भी है।

इस काम को कभी सीखा नहीं

ग्रेजुएशन कर चुकीं आफिया कहती हैं कि, मुझे ठीक से नहीं याद कि मेरी उम्र क्या थी जब मुझे अब्ब् के इस काम में दिलचसपी हुइ थी। तीसरी या चौथी क्लास में पुढ़ती थी और अब्बू के पास आकर बैठ जाती थी। वह सुबह से अपना काम शुरू कर देते थे और मैं स्कूल से आते ही अब्बू के पास बैठ कर उन्हें देखा करती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैंने कभी इस काम को सीखा नहीं बल्कि देखते देखते आ गया। अब मैं इसका पूरा काम जानती हूं। मार्केट भी अब मैं देखती हूं। मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है हुनरजादी क्रिएशन।

पुशतैनी हुनर को अपडेट करा है

आफिया कहती हैं कि नवाबों के दौर से चला आ रहा चांदी की जूतियों का चलन अब आम नहीं है। अब इन चप्पलों को दुलहनों के लिए बनवाया जाता है। शहर में आज भी हुनरपसंद और शौकीन लोगों

की कमी नहीं है। पहले यह चप्पलें एक सेट डिजाइन और सांचें पर बनी थीं लेकिन मैंने इन्हें काफी अपडेट किया है। पहले एक ही हील होती थी जिसे मैरीजैम हील कहते थे। लेकिन वह मुझे खुद कम्फर्टेबल नहीं लगती थी। आगे पीछे से बराबर मोटी हील होती थी। अब मैंने इन चप्पलों को फ्लैट हील में बनाना शुरू किया है। इन्हें नए-नए डिजाइन देती हूं। अब तो कई लोग मेरे डिजाइन की नकल कर रहे हैं। यह काम भी कस्टमाइज होता है। क्लाइंट को जितने वजन चांदी की चप्पल चाहिए, या फिर किस रंग के नंग जड़ना है क्लांइट की डिमांड पर बन जाता है। कुछ ही दिन पहले आधा किलो चांदी की एक जोड़ी चप्पल हमने बनाई थी। वैसे एक जोड़ी चप्पल में कम से कम दस ग्राम चांदी की जरूरत होती है। इसके बाद अगर क्लांइट चाहे तो वजन को बढ़ा सकता है लेकिन दस ग्राम से कम में नहीं होनी चाहिए। अब हमने हुनरजादी क्रिएशंस को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है।

शुरू में चुनौतियां भी थीं

इस वक्त अपने पिता और भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हुनरजादी क्रिएशंस को नई पहचान देने वाली आफिया कहती हैं कि जब मैं शुरू में मार्केट में अपने काम को लेकर जाती थी तो लोगों के सवाल परेशान कर देते थे। कोई अब्बू से कहता कि अरे लड़की को इस काम में क्यों लगा दिया? लड़का तो संभाल लेगा। कोई मुझसे पूछता कि अरे यह काम क्यों करती हो घर का काम करना है तुम्हें तो। खाना बनाना भी जानती हो यही काम करती हो? चांदी खरीदने जाती या फिर ऑडर पहुंचाने हर जगह लोग हैरत भरी नजरों से देखते थे। शायद इस लिए भी कि, एक तो इस हुनर के कारीगर ही अब शहर में ज्यादा नहीं है और कभी किसी लड़की ने इस काम को किया ही नहीं। मैं इकलौती लड़की हूं जो इस हुनर को कर रही हूं। अब तो लखनऊ और शहर के बाहर भी एग्जिबीशन में हिस्सा लेती हूं। लोग अब मुझे मेरे इस हुनर की वजह से पहचान रहं हैं।

****

लेखिका : मीडिया मैप की लखनऊ संवादाता हैं।

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link: www.mediamap.co.in

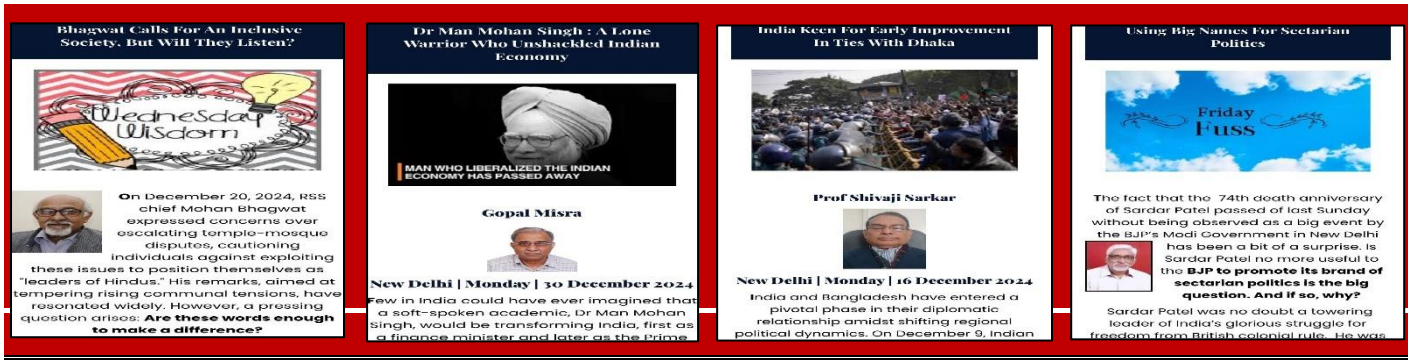

View Media Map YouTube

Media Map News

vol- 1002, 13 jan 25, ep- 59 : महाकुंभ में संत तीर्थयात्री सीवरेज के पानी में नहाने...

vol-1002, 11 jan 25, ep- 58 : महाकुंभ में कई वेशभूषा में बाबा

vol-1002, 9 jan 25, ep-57: मुस्लिम भी इलाहाबाद पुर्ण महाकुंभ में कल्पवास कर...

vol- 1002, 4 jan 2025, ep- 56: Media Map: Youtube meeting

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 43812481024***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक
MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय
फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

Advt.

Please stay with us and explore the beauty of the surrounding areas .

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com